साप्ताहिक

युवा प्रदेश

Freedom Of Speech

RNI NO. MPHIN/2015/76288

संपादक-नागेश नरवरिया

वर्ष 7, अंक-46 | www.yuvapradesh.in | भोपाल, शुक्रवार 23 दिसंबर 2022 | ypnews24@gmail.com | पृष्ठ -8 | मूल्य 2 रुपये

Mother's Basket
Kitchen Herbs & Spices
Swad jo pahuche dil tak

सुविचार

समय का उत्तम उपयोग करना सीखें क्योंकि विश्व के ज्यादातर सफल मनुष्यों ने इसी का प्रयोग किया है।

फसल चक्र की समय सीमा में होगी बढ़ोतरी

किसानों को कर्ज चुकाने के लिए मिलेगा दोगुना समय, डिफॉल्टर्स की संख्या घटेगी

भोपाल। नए साल के पहले मध्यप्रदेश में अब किसानों को कर्ज चुकाने के लिए दोगुना समय मिल सकता है। दरअसल मप्र सरकार फसल चक्र की समय सीमा बढ़ाने जा रही है। इसके तहत अल्पावधि में पकने वाली फसलों गेहूं, चना, धान आदि के लिए यह फसल चक्र या क्रॉप सीजन 12 माह का होगा, जबकि लंबी अवधि में पकने वाली गन्ने और केले की फसल के लिए सीमा 18 माह तय होगी। अभी तक अल्पावधि फसलों के लिए फसल चक्र 4-6 और लंबी अवधि की फसलों के लिए 8-9 माह होता है। मप्र में बैंक किसानों को अल्पकालीन फसलों के

लिए कर्ज चुकाने के लिए दो फसल चक्र और लंबी अवधि की फसलों के लिए एक फसल चक्र की मोहलत देती है। इसके बाद कर्ज की राशि डूबत खातों या एनपीए में डाल दी जाती है। किसान को अगली फसल के लिए बैंक कर्ज नहीं देते। सोसायटियों से क्रेडिट पर खाद-बीज नहीं मिलता।

मजबूरन किसानों को साहूकारों से कर्ज लेकर नकद में खाद बीज खरीदना पड़ता है। जानकारों का कहना है कि प्रदेश में कहीं फसल जल्दी पकती है, कहीं विलंब से। किसानों की शिकायत रहती है कि बैंक फसल कटने के बाद उसे उचित मूल्य पर बेचने तक का समय नहीं देते। किसानों को सस्ते दामों में उपज बेचकर बैंकों का कर्ज चुकाना पड़ता है। यह न करने पर किसान डिफॉल्टर हो जाते हैं। लेकिन एक अब निश्चित पैमाने पर फसल चक्र की गणना होगी।

भारत में लॉकडाउन का खतरा नही, पीएम मोदी की अपील-

मास्क जरूर पहनें; राहुल गांधी बोले- कुछ भी हो यात्रा नहीं रुकेगी

एजेंसी/ नई दिल्ली। सबसे पहले बात सबसे बड़े खतरे की। कोरोना का नाम सुनते ही हमारे जेहन में पहला शब्द लॉकडाउन आता है। अगर आप सोच रहे हैं कि कोरोना के साथ-साथ लॉकडाउन का भी खतरा है तो बेफिक्र हो जाइये। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के डॉक्टर अनिल गोयल ने कहा है कि भारत में लॉकडाउन की जरूरत नहीं पड़ेगी। IMA के मुताबिक, चीन की तुलना भारत के लोगों की इम्यूनिटी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। भारत की 95त्न आबादी में कोरोना के खिलाफ इम्यूनिटी बनी है, ऐसे में देश में लॉकडाउन नहीं लगेगा। इधर, भारत में कोरोना के खतरे को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रिव्यू मीटिंग की।मोदी ने मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग की अपील की। उन्होंने टेस्टिंग बढ़ाने और कोविड सैंपल की जीनोम सीक्वेंसिंग कराने पर जोर दिया। इस बीच केंद्र सरकार ने इंटरनेशनल ट्रेवलर्स के लिए गाइडलाइंस भी जारी कर दी है। अब बात कोरोना पर राजनीति की। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने 20 दिसंबर को राहुल गांधी को चिट्ठी लिखकर राहुल से यात्रा रोकने की अपील की थी। इसका जवाब राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान रैली में दिया।

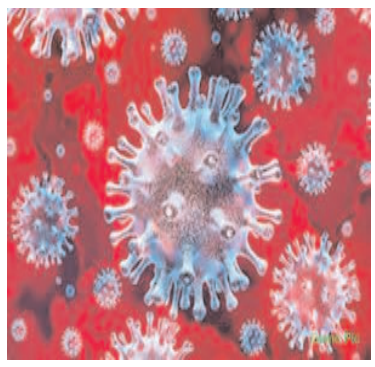

5 बड़ी खबरें, जो आपको अपडेट रखेंगी

1. पहले टेस्ट में मैन ऑफ द मैच रहे कुलदीप यादव दूसरे से बाहर, एक्सपर्ट ने पूछा- किस गलती की सजा दी बांग्लादेश के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच के लिए जब भारत की प्लेइंग-11 घोषित हुई तो फैंस से लेकर एक्सपर्ट तक सब हैरान रह गए। इसमें कुलदीप यादव का नाम शामिल नहीं था। कुलदीप ने पहले टेस्ट में 8 विकेट लिए थे और 40 रन की उपयोगी पारी खेली थी। इस शानदार प्रदर्शन के लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया था। चोटिल रोहित शर्मा की गैरहाजिरी में केएल राहुल इस सीरीज में टीम इंडिया की कप्तानी कर रहे हैं।

अफगानिस्तान में महिलाओं को घरों में कैद करने की कोशिश

काबुल। अफगानिस्तान में तालिबान शासन महिलाओं के अधिकारों का बर्बरतापूर्वक दमन कर रहा है। बीते साल अगस्त में तालिबान ने सत्ता पर कब्जा करने के बाद ही शिक्षा, नौकरियों और उनकी आवाजाही पर प्रतिबंध लगाकर महिलाओं को घरों में कैद करने के लिए नियमों में बदलाव करने शुरू कर दिए थे।

फैसले लागू करने मौलवियों का सहारा लिया: दुनिया को दिखाने के लिए अपने फैसले लागू करने के लिए मौलवियों का सहारा लिया। उनकी सरकारी और प्राइवेट नौकरियों पर रोक लगवा दी। आगे बढ़ने से रोकने के लिए तालिबान सुरक्षाबलों ने महिलाओं को डराया, धमकाया, हिरासत में लेने से लेकर अगवा तक किया गया।

अफगानिस्तान की महिला अधिकार कार्यकर्ता खदीजा अहमदी ने बताया कि तालिबान ने महिलाओं को जज या वकील के रूप में कोर्ट में प्रैक्टिस करने से रोक दिया है। सत्ता पर कब्जा करने से पहले अफगानिस्तान में लगभग 300 महिला जज थीं।

क्या विधवा संतानहीन महिला अपने पति के हिस्से में मिली संपत्ति अपने भाई के बच्चे को दे सकती है जानिए महत्वपूर्ण जजमेंट

जब किसी महिला का पति मर जाता है एवं उनकी कोई संतान नहीं होती है तब हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम,1956 की धारा 8 में बताया गया है कि प्रथम सूची के अनुसार मृत पति की संपत्ति की हकदार उसके पुत्र एवं पुत्रियां होते हैं अगर वह संतान हीन था तो उसकी संपत्ति की हकदार उसकी विधवा पत्नी होती है। सवाल यह है कि क्या विधवा पत्नी पति से प्राप्त हुई संपत्ति उसके भाई के लड़के को दे सकती है? जानते हैं सुप्रीम कोर्ट का महत्वपूर्ण निर्णय। खुशी राम और अन्य बनाम नवल सिंह और अन्य(निर्णय वर्ष 2020)- उक्त मामले में में उच्चतम न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया कि कोई भी हिन्दू विधवा महिला अपने पति के हिस्से की संपत्ति जो उसे उत्तराधिकार के अंतर्गत प्राप्त हुई है, वह अपने भाई के पुत्रों को दे सकती है क्योंकि ऐसे व्यक्ति हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम,1956 की धारा 15(1)(घ) के अंतर्गत विधवा महिला के विधिक उत्तराधिकारी हो सकते हैं एवं यह अपरिचित नहीं माने जा सकती है।

मामले का सार- उक्त मामले में आपत्तिकर्ता ने आपत्ति लगाई थी की विधवा महिला की संपत्ति पति के वारिस को प्राप्त हो क्योंकि उक्त अधिनियम की धारा 15 के अनुसार हिन्दू महिला की संपत्ति उत्तराधिकार के नियम के अनुसार

(क). उसके पुत्र/पुत्रियों एवं पति को।
(ख). पति के वारिसों को
(ग). माता पिता को।
(घ). पिता के वारिसों को।
(ङ). माता के वारिसों को।

क्रम के अनुसार विधवा संन्तान हीन महिला की संपत्ति पर पति के वारिसों का अधिकार होगा न की महिला के भाई के पुत्रों का लेकिन उच्चतम न्यायालय द्वारा मार्गदर्शन निर्णय 1. काले एवं अन्य बनाम उपनिदेशक चकबन्दी(निर्णय वर्ष 1976).

2. रामचरन दास बनाम गिरजानंदिनी देवी और अन्य(निर्णय वर्ष 1965)।

में न्यायालय द्वारा स्पष्ट किया गया था कि महिला उत्तराधिकारी संबंधित संपत्ति के अधिकार में अपीलों में मेरिट नहीं देखी जाती है अर्थात महिला स्वयं की इच्छा से अपने किसी भी विधिक उत्तराधिकारी को अपने पति की संपत्ति दे सकती है।

?? लेखिका श्रीमती ज्योति सिंह चौहान(जिला संवाददाता युवा प्रदेश समाचार पत्र अलीगढ़ उत्तर प्रदेश एवं महिला सामाजिक कार्यकर्ता)

जानिए सभा एवं सम्मेलन, करने का मौलिक अधिकार क्या है एवं कब इस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है/Fundamental of Right.....

सभा एवं सम्मेलन करना लोकतंत्र में एक सहज एवं स्वाभाविक बात है।इसके माध्यम से एक दूसरे में विचारों का आदान प्रदान किया जाता है। इसी कारण कभी-कभी इसे वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के साथ जोड़ दिया जाता हैं या कहे तो दोनो एक दूसरे के पूरक होते हैं। सभा एवं सम्मेलन विचारों की अभिव्यक्ति का एक सशक्त माध्यम समझा जाता है क्योंकि प्रकाशन को छोड़कर विचारों की अभिव्यक्ति का दूसरा कोई अच्छा माध्यम यही है इसलिए भारतीय संविधान में इसे मौलिक अधिकार के रूप में सम्मिलित किया गया है जानिए।

भारतीय संविधान अधिनियम,1950 का अनुच्छेद 19(1)(ख) की परिभाषा?

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(ख) भारतीय नागरिकों को शांतिपूर्ण तरीके से बिना हथियार के सभा या सम्मलेन की स्वतंत्रता प्रदान करता है, इसमें सार्वजनिक सम्मलेन, प्रदर्शन, जुलूस, सभाएं को भी सम्मिलित किया गया है।

सभा एवं सम्मेलन के अधिकार की शर्तें:-

1. सभा या सम्मेलन शांतिपूर्ण होना चाहिए।
2. यह बिना हथियारों के होना चाहिए।
3. यह देश(राज्य) की प्रभुता, एकता और अखंडता एवं लोक-व्यवस्था,लोकशान्ति के प्रतिकूल नहीं होना चाहिए।

अर्थात उपर्युक्त शर्तो के अधीन भारत का प्रत्येक नागरिक सभा, सम्मेलन, प्रदर्शन आदि कर सकता है एवं यह उनका संवैधानिक अधिकार होगा।

?? लेखक बीआर अहिरवार(एडवोकेट एवं विधिक सलाहकार होशंगाबाद) 9827737665

मातृ शक्ति एवं बुजुर्गों का सम्मान ईश्वर की अर्चना के समरूप- कलेक्टर

कैलाश वर्मा ❑ शहडोल

सुशासन सप्ताह के अन्तर्गत वृद्धाश्रम में कलेक्टर की उपस्थिति में हुई साफ-सफाई एवं स्वच्छता की पहल

मातृ शक्ति एवं बुजुर्गों का सम्मान ईश्वर की पूजा एवं अर्चना के समान होती है, सभी को अपने बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए, जब बच्चे छोटे होते है तो मॉ-बाप उनका लालन-पालन पूरे मनोयोग एवं समर्पित भाव से करते है। मॉ-बाप के वृद्व होने पर बच्चों का कर्तव्य है कि उसी निष्ठा के साथ अपने मॉ-बाप की सेवा करें। उक्त उद्बोधन जनपद पंचायत सोहागपुर के ग्राम पंचायत कल्याणपुर में स्थित वृद्धाश्रम में आयोजित सुशासन सप्ताह के तहत कार्यक्रम में कलेक्टर श्रीमती वंदना वैद्य ने दिये। इस अवसर पर कलेक्टर ने वहां के वृद्वजनों से उनके स्वास्थ्य एवं उन्हें मिल रही सुविधाओं की जानकारी भी प्राप्त की। वृद्धाश्रम में रह रहे वृद्वजनों से उन्हें वृद्वा पेंशन के बारे में भी जाना और उपस्थित अधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी को वृद्वा पेंशन का लाभ मिलना चाहिए जिनका आधार कार्ड़ लिंक नही है उन्हें जुड़वाकर उन्हें वृद्वा पेंशन दिलवाया जाएं। कलेक्टर ने तिलक लगाकर एवं कंबल देकर चंद्रा सिंह, कमला, आशा गुप्ता सहित वृद्वजनों को सम्मानित भी किया सुशासन सप्ताह के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में कलेक्टर की पहल पर जन अभियान परिषद के सदस्यों तथा नगरपालिका शहडोल के कर्मचारियों

द्वारा वृद्धाश्रम में साफ-सफाई एवं स्वच्छता की गई। कलेक्टर ने उप संचालक सामाजिक न्याय को निर्देशित किया कि वृद्धाश्रम की व्यवस्थाए सुदृढ़ करने के लिये हाल बाउण्ड्री फिनिसिंग, पेवर्स ब्लाक्स लगाकर परिसर व्यवस्थित कराये। साथ ही शौचालय आदि की व्यवस्था भी करा दें तथा क्यारियां आदि बनाकर साग एवं सब्जियां लगवायें तथा समय-समय पर उनकी देखभाल भी हो। कलेक्टर ने वहा रह रहे मातृ शक्तियों एवं बुजुर्गों के साथ बैठकर वृद्धाश्रम के बारे में चर्चा की। कलेक्टर को वृद्धाश्रम में रह रही वृद्व माता ने सुझाव दिया कि वृद्धाश्रम में रहने वाले हम सभी समय-समय

पर बागवानी आदि का कार्य करे जिससे हमारा शारीरिक एवं मानसिक संतुलन बना रहेगा। इस पर कलेक्टर ने उनके सुझाव की प्रषंसा की तथा कहा कि वृद्धाश्रम पॉलिथिन आदि ईधर-ऊधर न फेंका जाए बल्कि डस्टबीन में डाला जायें। जिससे वृद्धाश्रम में रहने वाले बुजुर्गों को किसी भी प्रकार की परेषानियों का सामना न करना पड़े। कलेक्टर ने कहा कि समय-समय पर वे वृद्धाश्रम का निरीक्षण कर उन्हें मिल रही सुविधाओं की जानकारी लेंगी और उनके स्वास्थ्य की जांच भी षिविर लगाकर कराया जाएगा। कलेक्टर ने उप संचालक सामाजिक न्याय को निर्देषित किया कि वृद्धाश्रम में रह रहे वृद्वजनों को ऐसा वातावरण मिलना चाहिए कि उन्हें घर परिवार एवं अपनों की कमी महसूस न हों। मीडिया से रूबरू होकर कलेक्टर श्रीमती वंदना वैद्य ने सुषासन सप्ताह में हो रही दिन -प्रतिदिन के गतिविधियों के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि 25 दिसम्बर तक चलने वाले साप्ताहिक कार्यक्रम में विभिन्न स्तरों पर लगातार आयोजित की जा रही है जिसमें नषा मुक्ति, स्कूलों के सामने से तम्बाकू, सिगरेट एवं गुटखा की दुकानों को हटाना एवं पेसा एक्ट की जानकारी जन मानस को देना एवं साफ-सफाई एवं स्वच्छता, जल संरक्षण सहित अन्य कार्य प्रषासन, जन अभियान परिषद, नवांकुर संस्था एवं ग्रामीणों के सहयोग से लगातार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हम सब मिलकर साफ-सुथरा एवं स्वच्छ समाज की स्थापना करेंगे और हमें पूर्ण विष्वास है इसमें हम सफल होंगें। इस अवसर पर उप संचालक सामाजिक न्याय श्री षिवेन्द्र सिंह, जन अभियान परिषद के जिला समन्वयक श्री विवेक पाण्डेय, जन अभियान परिषद के नवांकुर संस्था के सदस्यगण, वृद्धाश्रम में रह रहे राज वैद्य श्री एस.के. शर्मा, श्री तस्मीम खान, नगरपालिका मोती लाल सिंह, श्री धनंजय सिंह एवं अन्य कर्मचारी तथा मीडियाकर्मी उपस्थित थें।

जनता

यह जनता है भाई जनता यह मांगेगी जवाब।
तू है सरकारी नौकर भले होगा घर का नवाब।
बंद करो यह तानाशाही हमसे है सरकार।
यह जनता है भाई जनता यह मांगेगी जवाब।
तू है सरकारी नौकर भले होगा घर का नवाब।
लापरवाही भ्रष्टाचारी सब है आपके गहने।
काले धन से तन को ढकने श्वेत वस्त्र हैं पहने।
अरे घूम रहे कई भूखे नंगे रोटी से उधार।
यह जनता है भाई जनता यह मांगेगी जवाब।
तू है सरकारी नौकरी भले होगा घर का नवाब।
ईमानदार था समझ के हमने मुखिया तुझे बनाया।
दिया खजाना अपना तुझको जिम्मेदार बनाया।
बंदर बनकर रोटी खा गया करते रहे विचार।
यह जनता है भाई जनता यह मांगेगी जवाब।

बिजली कंपनी की 28 टीमों ने भोपाल शहर में की सघन चेकिंग

भोपाल। मध्यक्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा भोपाल शहर के विभिन्न इलाकों में बिजली का अवैध और अनधिकृत उपयोग करने वालों के खिलाफ सघन चेकिंग अभियान चलाकर विद्युत अधिनियम 2003 की विभिन्न धाराओं में 169 प्रकरण बनाये गये है। इस अभियान में कंपनी द्वारा भोपाल शहर के अधिक विद्युत हानियों वाले क्षेत्रों टीला जमालपुरा, शारदा कॉलोनी, काजी कैंप, सलीम चौक, गणगौर की बाबड़ी, अटल नेहरू नगर, शंकर नगर, शिव नगर एवं बाग उमराव दूल्हा क्षेत्र में बिजली कंपनी की 28 टीमों ने सघन चेंकिंग अभियान चलाकर विद्युत अधिनियम 2003 की विभिन्न धाराओं में सीधे बिजली चोरी, मीटर से छेड़छाड़ एवं भार परिवर्तन के प्रकरण बनाये। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के महाप्रबंधक शहर वृत्त भोपाल श्री जाहिद अजीज खान ने बताया कि कंपनी द्वारा अवैध कनेक्शन की जांच और अनधिकृत बिजली का उपयोग करने वालों के खिलाफ सघन चेकिंग अभियान चलाकर विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 126 एवं 135 के तहत कार्यवाही की जा रही है। भोपाल शहर के विभिन्न इलाकों में आज कंपनी की 28 टीमों ने विद्युत अधिनियम 2003 की विभिन्न धाराओं में 169 प्रकरण बनाकर कार्यवाही की। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने आमजन एवं उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे वैध कनेक्शन लेकर ही बिजली का उपयोग करें और बिजली बिलों का समय पर भुगतान करें। बिजली चोरी जैसे सामाजिक अपराध को रोकें एवं बिजली का अवैध और अनधिकृत उपयोग न करें। बिजली चोरी के मामलों में विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 126, 135 एवं 138 में बनने वाले मुकदमों और अप्रिय कार्रवाई से बचें। उल्लेखनीय है कि बिजली चोरी के प्रकरणों में आरोप सिद्ध पाये जाने पर जुर्माना या कारावास या दोनों का प्रावधान है।

विद्युत अधिनियम की धाराओं के तहत 169 प्रकरण बनाये गये

शासन आधारित न होकर आत्म-निर्भर हो संगठन, ऐसे प्रयास किए जाएं

भोपाल। स्कूल शिक्षा (स्वतंत्र प्रभार) एवं सामान्य प्रशासन राज्य मंत्री श्री इन्दर सिंह परमार की अध्यक्षता में आज मंत्रालय में भारत स्काउटस एवं गाइड्स मध्यप्रदेश राज्य परिषद की बैठक हुई। बैठक में एजेंडे के विभिन्न बिंदुओं एवं प्रस्तावों पर चर्चा हुई। श्री परमार ने स्काउट्स एवं गाइड्स के सभी डॉक्यूमेंट, रूपरेखा, कार्यक्रम, बैठक एवं अन्य गतिविधियों को हिंदी भाषा में संपादित किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि भारत स्काउटस एवं गाइड्स मध्यप्रदेश संगठन, शासन आधारित संगठन होने के बजाय आत्म-निर्भर संगठन की भांति स्थापित हो सके, इस दिशा में प्रयास करने की आवश्यकता है। संगठन के आर्थिक पक्ष को मजबूत करने पर भी विचार मंथन किया गया। राज्य सचिव श्री राजेश प्रसाद मिश्रा ने राज्य परिषद की बैठक का पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। विगत राज्य कार्यकारिणी बैठक में पारित किए गए प्रस्तावों को सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया। विगत वर्ष के वार्षिक प्रतिवेदन का और संगठन के बजट का भी अनुमोदन किया गया। सत्र 2022-23 के वार्षिक कार्यक्रम एवं वार्षिक योजना का अनुमोदन किया गया। इसमें विद्यालय से लेकर राज्य स्तर के आयोजनों का कैलेंडर जारी किया जाएगा। राज्य मुख्य आयुक्त श्री पारस चंद्र जैन, राज्य कोषाध्यक्ष श्री रमेशचंद्र शर्मा, राज्य उपाध्यक्ष श्री अजय मिश्रा, राज्य आयुक्त (कब) श्री डी.एस. राघव, राज्य आयुक्त (रोवर) श्री राजीव जैन सहित स्काउटस एवं गाइड्स के विभिन्न पदाधिकारी उपस्थित रहे। प्रदेश के विभिन्न जिलों के पदाधिकारी एवं अधिकारी वर्चुअली जुड़े।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत के सदस्यों के साथ रोपे पौधे

भोपाल। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत के सदस्यों के साथ स्मार्ट सिटी उद्यान में करंज, खिरनी और सारिका इंडिका के पौधे लगाए। मुख्यमंत्री श्री चौहान के साथ श्री आशीष शर्मा ने अपने जन्म-दिवस पर पौध-रोपण किया। मुख्यमंत्री ने उन्हें जन्म-दिवस की शुभकामनाएँ और बधाई दी।

अंतर्राष्ट्रीय वन मेले में लघु वनोपज से आत्म-निर्भरता विषय पर हुई कार्यशाला

भोपाल। उत्तराखण्ड के वन मंत्री श्री सुबोध उनियाल ने कहा है कि जंगल लोगों की आजीविका से जोड़ने और जंगल को बचाने के लिए वर्तमान में बड़ा यक्ष प्रश्न है। वन मंत्री श्री उनियाल अंतर्राष्ट्रीय वन मेला भोपाल में लघु वनोपज से आत्म-निर्भरता विषय पर दो दिवसीय कार्यशाला को सम्बोधित कर रहे थे। श्री उनियाल ने कहा कि जंगल का निर्माण आपसी सहयोग से संभव हुआ है, इसीलिए हमें जंगल बचाने में समुदाय सहभागिता पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। उन्होंने कान्फ्रेंस में विभिन्न आयुर्वेदिक और वन-शिक्षण संस्थाओं से शामिल हुए विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि दुनिया का कोई लक्ष्य आपकी हिम्मत से बड़ा नहीं हो सकता। राज्य लघु वनोपज संघ के एमडी श्री पुष्कर सिंह ने बताया कि दो दिन तक चलने वाली कार्यशाला में देश-विदेश में हुए विभिन्न अनुसंधानों की जानकारी मिलेगी, जो आयुर्वेद के विद्यार्थियों के लिए ज्ञानवर्धक साबित होगी। प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख श्री आर.के. गुप्ता ने बताया कि वन मेले में लगे स्टालों से प्रदेश की जैव विविधता झलकती है। यहाँ एक ओर पातालकोट का विश्व विख्यात शहद, झाबुआ का लाल चावल, महाकौशल क्षेत्र का कोदो-कुटकी और कई तरह के पारम्परिक औषधीय पौधों की प्रचुरता है। कार्यशाला में नेपाल, इंडोनेशिया, भूटान के विशेषज्ञों के साथ मध्यप्रदेश सहित उत्तराखण्ड, उत्तरप्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, महाराष्ट्र और हिमाचल प्रदेश के विषय-विशेषज्ञ, अधिकारी और इंडस्ट्री एक्सपर्ट शामिल हुए।

कक्षा में बच्चों की कॉपी और वर्कशीट की जाँच विषय पर हुआ राज्य स्तरीय शैक्षिक संवाद

भोपाल। सीएम राइज शिक्षक व्यावसायिक उन्नयन कार्यक्रम में राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा कक्षा में बच्चों की कॉपी और वर्कशीट की जाँच÷ विषय पर 5वां राज्य स्तरीय शैक्षिक संवाद किया गया। इसमें राज्य शिक्षा केंद्र के एडूसेट से 5 जिलों के चयनित प्रतिभागी प्रत्यक्ष रूप से और अन्य जिलों के डाइट सदस्य, ज़िला परियोजना समन्वयक, अतिरिक्त परियोजना समन्वयक, अकादमिक की रिसोर्स पर्सन, राज्य एवं ज़िला स्तरीय रिसोर्स पर्सन वर्चुअली शामिल हुए। चर्चा में प्रतिभागियों ने नोटबुक की जाँच की आवश्यकता, नोटबुक से विद्यार्थी के विषय में मिलने वाली जानकारी, नोटबुक के उपयोग, जाँच का नियमितिकरण एवं नोटबुक की जाँच से सम्बन्धी समस्याएँ आदि बिंदुओं पर केंद्रित चर्चा की। विभिन्न ज़िलों के शिक्षकों ने अनेक सकारात्मक सुझावों से उत्सुकता और उत्साह के साथ संवाद में सहभागिता की। संवाद में मुख्य रूप से राज्य शिक्षा केंद्र के अपर संचालक श्री लोकेश जांगिड़, नियंत्रक पाठ्यचर्या श्री अशोक पारीक, नियंत्रक शिक्षक शिक्षा प्रकोष्ठ श्री मनोज गुहा सहित शिक्षण प्रशिक्षण में सहयोगी संस्था पीपल के सदस्य शामिल हुए। उल्लेखनीय है कि दीक्षा पर प्रारम्भ किए गये नवीन कोर्स और मिशन अंकुर में संचालित कोर्स प्रदेश के शिक्षकों द्वारा पूर्ण किए जा रहे हैं। राज्य शिक्षा केंद्र से जारी पत्रानुसार आगामी दिनों में ज़िला स्तरीय शैक्षिक संवाद किया जाएगा।

प्रषिक्षणार्थियों को पूर्ण रूप से पारंगत करें प्रषिक्षक- कलेक्टर

बैगा महिलाएं कालीन बनाने का प्रषिक्षण प्राप्त कर हो रही स्वावलंबी

शहडोल। आदिवासी बाहुल्य जिले में महिलाओं को स्वावलंबन की राह में बढाने तथा स्वरोजगार देने के उदेष्य से एवं उन्हें आर्थिक रूप से सषक्त करने के लिये कलेक्टर श्रीमती वंदना वैद्य लगातार प्रयास कर रही है। ग्राम पचडी में जहां हस्तषिल्प एवं हथकरघा केन्द्र छतवई के द्वारा ग्रम पचडी गांव में एकीकृत कलस्टर विकास योजना के अन्तर्गत 50 दिवसीय प्रषिक्षण आयोजन किया जा रहा है। आज कलेक्टर श्रीमती वंदना वैद्य ने जिले के जनपद पंचायत सोहागपुर के ग्राम पचडी में दरी कालीन उत्पादन केन्द्र पचडी का निरीक्षण किया।

प्रषिक्षण षिविर में 20 बैगा महिलाएं कालीन एवं दरी बनाने का प्रषिक्षण प्राप्त कर रही थी। कलेक्टर ने प्रषिक्षक एवं प्रषिक्षणार्थियों से प्रषिक्षण के संबंध में जानकारी प्राप्त की और कहा कि सभी प्रषिक्षणार्थी पूर्ण लगन से प्रषिक्षण प्राप्त करे और कालीन एवं दरी बनाने में पूर्ण पारंगत हो जाए जिससे वे अपने घर पर ही कालीन एवं दरी बनाने का कार्य कर सकें। कलेक्टर ने कहा कि हस्तषिल्प कला हथकरघा उद्योग एवं कुटीर एवं ग्रामोद्योग के द्वारा महिलाएं सषक्त होकर अपने परिवार की आर्थिक स्थिति में सुधार कर अपना जीवन स्तर सुधार सकती है। उन्होंने कहा कि प्रषिक्षणार्थियों को दरी एवं कालीन बनाने में किसी भी प्रकार की कठिनाई न हो इस बात का अधिकारी विषेष ध्यान रखें। उन्होंने हस्तषिल्प हथकरघा के प्रभारी को निर्देषित किया कि प्रषिक्षणार्थियों को उनकी मांग के अनुसार कच्चा माल एवं उपकरण तथा मार्गदर्षन दिया जाए। जिससे उन्हें घर पर ही उन्हें स्वरोजगार प्राप्त हो सकें। इस अवसर पर आजीविका मिषन के श्री विष्णूकांत विष्वकर्मा एवं प्रभारी दरी कालीन उत्पादन केन्द्र पचडी श्री षिवषंकर पाण्डेय उपस्थित थें।

बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा प्रभारी ने प्री प्राइमरी कक्षाओं के संचालन एवं गतिविधियों का किया औचक निरीक्षण

कैलाश वर्मा ❑ शहडोल

राज्य शिक्षा केन्द्र के निर्देशानुसार शहडोल जिले की प्रभारी श्रीमती अर्चना कुलश्रेष्ठ त्रि दिवसीय दौरे पर शहडोल आई है जिसके प्रथम दिन आज जिले में संचालित प्री प्राइमरी कक्षाओं के संचालन एवं गतिविधियों का औचक निरीक्षण किया। ज्ञातव्य हो कि जिले के अन्तर्गत 297 शासकीय प्राथमिक विद्यालयों मे प्री प्राइमरी(केजी-1 एवं केजी-2) की कक्षाओ का संचालन वर्ष 2019-20 से प्रारम्भ किया गया है। वर्ष 2020-21 एवं वर्ष 2021-22 मे कोविड महामारी मे पूर्व प्राथमिक कक्षाओ के संचालन की अनुमति नही थी वर्ष 2022-23 में उक्त कक्षाये संचालित हुई राज्य शिक्षा केन्द्र के निर्देशानुसार सभी प्री प्राइमरी कक्षाओं के शिक्षको को प्रशिक्षण प्रदान किया गया साथ में शिक्षक मार्गदर्शिका जिसमें लेसन प्लान एवं पढ़ाने के तरीकों को विस्तार से बतलाया गया है। जिले के भ्रमण के दौरान प्री-

प्राइमरी स्कूलों के संचालन एवं गतिविधियों की जानकारी प्राप्त करने के लिये आज बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा (ई.सी.सी.ई.) प्रभारी श्रीमती अर्चना कुलश्रेष्ठ ने शासकीय माध्यमिक विद्यालय जमुई, शासकीय प्राथमिक पाठशाला कट्ठी टोला एवं शासकीय प्राथमिक शाला वार्ड न. 03 शहडोल का अवलोकन किया गया तीनों विद्यालयों में शिक्षकों द्वारा कराये जा रहे गतिविधियों से प्रसन्नता व्यक्त की गई। सर्वप्रथम माध्यमिक विद्यालय जमुई में उपस्थित हुई प्री प्राइमरी मे दर्ज 23 मे 21 बच्चे उपस्थित रहे। शिक्षिका श्रीमती सपना चतुर्वेदी द्वारा अबाकॅस एवं एलईडी टीव्ही मे चलचित्र के माध्यम से गिनती सिखाने की गतिविधि कराई जा रही थी प्राथमिक विद्यालय कट्ठी टोला मे प्री प्राइमरी मे दर्ज 9 मे 07 बच्चे उपस्थित रहे यहा पर शिक्षिका श्रीमती बबिता प्रजापति द्वारा खिलौने एवं नृत्य द्वारा गतिविधि कराई जा रही थी। विद्यालय परिसर मे बने बालवाटिका एवं किचन गार्डन के देखकर प्रसन्नता व्यक्त की गई। प्राथमिक शाला वार्ड न. 03 शहडोल दर्ज 12 मे 10 छात्र उपस्थित रहे सभी बच्चो के द्वारा अपना नाम एवं नाम के प्रथम अक्षर से बनने वाले शब्दो के बड़े रोचक विधि से बतलाया गया।

आवश्यकता

युवा प्रदेश नेटवर्क

मध्यप्रदेश के सभी जिले व तहसीलों में संवाददाता नियुक्त किये जाने है। इच्छुक व्यक्ति संपर्क करें।

युवा प्रदेश नेटवर्क,
प्रधान संपादक-नागेश नरवरिया
मो.- 9425156055-9755364204

विद्यालय के आसपास से हटाई गई तम्बांकू, सिंगरेट, गुटखा विक्रय की दुकानें

शहडोल। जिले के समस्त विकासखंडो में कलेक्टर श्रीमती वंदना वैद्य के मार्गदर्शन में सुशासन सप्ताह मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में आज विकासखंड सोहागपुर के ग्राम पंचायत जमुई में शासकीय माध्यमिक विद्यालय जुमई के विद्यार्थियों, शिक्षकगण सहित अन्य लोगों को उप संचालक सामाजिक न्याय श्री शिवेन्द्र सिंह द्वारा नशा मुक्ति की शपथ दिलाई गई। शपथ दिलाते हुए कहा गया जिंदगी को कहे हां और नशे को कहे ना, जागरूकता का उठा के ढाल बनाएंगे हम नशा मुक्त शहडोल, नशा किसी मादक पदार्थ या मादक द्रव्य के सेवन से संबंध ऐसी मानसिक एवं शारीरिक निर्भरता से जो प्राय- स्वैच्छिक नियंत्रण से परे होती है, किसी घर का चिराग न बुझने पाए, नशे की आग को हम जो बुझाऐं। साथ ही विद्यालय के सामने बेचे जा रहे सिगरेट, तम्बाकू के दुकानों को भी हटवाया गया। सुशासन सप्ताह के अन्तर्गत जन अभियान परिषद के जिला समन्वयक श्री विवेक पाण्डेय की अगुवाई में सोहागपुर के ग्राम पंचायत छतवई में पेसा एक्ट के प्रति लोगों को जागरूक करने हेतु कार्यक्रम आयोजित किया गया। पेसा एक्ट जागरूकता कार्यक्रम में लोगों को बताया गया कि ग्रामसभा की सहमति के बिना अनुसूचित क्षेत्रों में नई शराब दुकान नहीं खुलेगी तथा पेसा एक्ट लागू होने से ग्रामों को तालाबों के प्रबंधन का अधिकार मिला वही ग्राम पंचायत 100 एकड़ तक की सिंचाई क्षमता के जलाशयों का प्रबंधन करेगी, तालाब व जलाशयों में मछली पालन, सिंघाड़ा उत्पादन की गतिविधियों का अधिकार, होगी आमदनी में वृद्धि जलाशयों को प्रदूषित करने पर कार्यवाही का अधिकार भी मिला है। पेसा एक्ट जागरूकता कार्यक्रम में सरपंच श्री मती मुन्नी बैगा,सचिव रामशरण बैगा,पटवारी नेहा गुप्ता,पंच मोहनलाल महरा,गोला बैगा, सुरजदीन बैगा, कल्याणी बाजपेई, अरूण कुमार बाजपेई एवं ग्रामवासी उपस्थित रहे। इसी प्रकार सुशासन सप्ताह के तहत जनपद पंचायत जयसिंहनगर के ग्राम पंचायत मीठी में सीएम हेल्पलाइन के लंबित शिकायतों का निराकरण किया गया, नशा मुक्ति के संबंध में रैली निकाली गई सहित अन्य नवाचार भी किये गये।

विद्यार्थियों ने नशा मुक्ति की ली शपथ

ग्राम छतवई में हुआ पेसा एक्ट जागरूकता कार्यक्रम

मध्यप्रदेश विधानसभा मैं आजीविका मिशन की चर्चा

दिनांक 21/12/2022/8.41 बजे अध्यक्ष महोदय (श्री गिरीश गौतम) पीठासीन हुये. श्री कमलेश्वर पटेल-- माननीय मुख्यमंत्री जी आप विराजमान हैं और आपके सामने कोई बात हो रही है तो उम्मीद है कि आप उस पर तन्मयता से कार्यवाही भी करेंगे. जिस तरह से अभी हमने उल्लेख किया, समूह, संवाद, स्ट्रीट वेंडर संवाद के नाम पर 10 करोड़ से अधिक की राशि का व्यय हुआ है कोविड के टाइम में और यह गरीब महिलाओं के प्रशिक्षण के लिये राशि आती है. इसी विधान सभा कार्यवाही / 21 दिसंबर 2022 शोधित / प्रकाशन के लिए नहीं तरह प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम पर 30 करोड़ से ज्यादा राशि खर्च हुई है उन गरीब महिलाओं की जिनके जीविकोपार्जन के लिये उनके आर्थिक सुदृढ़ीकरण के लिये आजीविका मिशन 2011 में यूपीए सरकार ने, सोनिया जी ने शुरूआत की थी, पर आज वह राजनीतिक अखाड़ा हो गया है.

इसी तरह माननीय राष्टपति महोदय के कार्यक्रम में 3 करोड़ रूपये खर्च किये गये हैं तो आजीविका मिशन का भी हमारे कई साथी जिक्र कर रहे थे, यह बात सच है कि अगर कांग्रेस की सरकार रहती तो आजीविका मिशन की दीदीयों का कर्ज भी माफ होता और हम जो उनको 10 हजार रूपये भी अगर वह कर्ज लेती थीं 24 प्रतिशत ब्याज देना पड़ता था, उसको घटाकर हमने 12 प्रतिशत करने का काम किया था और जीरो प्रतिशत का 500 करोड़ का एक मद भी बनाया था और केबिनेट से प्रस्ताव भी पारित हो गया था पर दुर्भाग्य है जो बिना ब्याज के उनको पैसे जीरो परसेंट पर देते पर यह सरकार आने के बाद उसका इम्प्लीमेंट नहीं किया. क्या वजह है कि एक सेवानिवृत्त आईएफएस अधिकारी है जो वर्ष 2018 में रिटायर्ड हो गये थे, बार-बार उनकी सीईओ के रूप में नियुक्ति क्यों की जा रही है और एक ऐसी ईमानदार महिला जो वहां पर एडिशनल सीईओ थी, उसने जांच की और उसमें दोषी पाये गये, लोकायुक्त में प्रकरण दर्ज है, उन लोगों ने आवेदन दिया, शिकायत की हुई है, ईओडब्ल्यू में शिकायत की हुई है, विधान सभा की समिति में शिकायत की हुई है आज तक कार्यवाही करने की बजाय क्या मध्यप्रदेश में कोई ऐसा अधिकारी नहीं है, कोई आईएएस नहीं है जिसको हम सीईओ के पद पर आजीविका मिशन जैसे महत्वपूर्ण पद पर बिठा सकें, क्यों, क्योंकि चुनाव जिताने का उनके पास पता नहीं कौन सा आंकड़ा है और माननीय मुख्यमंत्री जी उनसे प्रभावित हो जाते हैं. आज स्थिति यह है कि दो वर्ष से स्कूल के बच्चों का गणवेश जो गरीब बच्चों के लिये शासकीय स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों का गणवेश वितरित नहीं हुआ है, सिर्फ इसी भ्रष्टाचार की वजह से और घटिया क्वालिटी के कपड़े खरीदे गये और महिलाओं को जो स्व-सहायता समूह को सिलाई करने के लिये देते हैं उनको मिला भी नहीं है बल्कि मार्केट से खरीद कर दिया जा रहा है और आज भी दो वर्षों से नहीं दिये गये हैं, इसकी जांच अगर निष्पक्ष हो जाये तो बहुत सारे लोग इसमें निपटेंगे और जो अधिकारी दोषी पाये जाते हैं जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के केस रजिस्टर्ड हैं उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं होती है, मेरे पास तो जांच रिपोर्ट भी है, माननीय अगर आप अनुमति दें तो हम इसको पटल पर भी रखने को तैयार हैं, जांच रिपोर्ट हैं जिसमें सीधे-सीधे नौकरियों की भर्ती में दोषसिद्ध हो रहा है नौकरियों की भरती में पर ऐसे अधिकारी के खिलाफ पता नहीं माननीय मुख्यमंत्री जी क्यों मेहरबान हैं, हम तो आपको ही बोलेंगे क्योंकि मुखिया आप हैं. हो सकता है आप मेहरबान न हों आपको कोई गलत जानकारी दे रहा हो विधान सभा कार्यवाही / 21 दिसंबर 2022 अशोधित / प्रकाशन के लिए नहीं तरह प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम पर 30 करोड़ से ज्यादा राशि खर्च हुई है उन गरीब महिलाओं की जिनके जीविकोपार्जन के लिये उनके आर्थिक सुदृढ़ीकरण के लिये आजीविका मिशन 2011 में यूपीए सरकार ने, सोनिया जी ने शुरूआत की थी, पर आज वह राजनीतिक अखाड़ा हो गया है. इसी तरह माननीय राष्टपति महोदय के कार्यक्रम में 3 करोड़ रूपये खर्च किये गये हैं तो आजीविका मिशन का भी हमारे कई साथी जिक्र कर रहे थे, यह बात सच है कि अगर कांग्रेस की सरकार रहती तो आजीविका मिशन की दीदीयों का कर्ज भी माफ होता और हम जो उनको 10 हजार रूपये भी अगर वह कर्ज लेती थीं 24 प्रतिशत ब्याज देना पड़ता था, उसको घटाकर हमने 12 प्रतिशत करने का काम किया था और जीरो प्रतिशत का 500 करोड़ का एक मद भी बनाया था और केबिनेट से प्रस्ताव भी पारित हो गया था पर दुर्भाग्य है जो बिना ब्याज के उनको पैसे जीरो परसेंट पर देते पर यह सरकार आने के बाद उसका इम्प्लीमेंट नहीं किया. क्या वजह है कि एक सेवानिवृत्त आईएफएस अधिकारी है जो वर्ष 2018 में रिटायर्ड हो गये थे, बार-बार उनकी सीईओ के रूप में नियुक्ति क्यों की जा रही है और एक ऐसी ईमानदार महिला जो वहां पर एडिशनल सीईओ थी, उसने जांच की और उसमें दोषी पाये गये, लोकायुक्त में प्रकरण दर्ज है, उन लोगों ने आवेदन दिया, शिकायत की हुई है, ईओडब्ल्यू में शिकायत की हुई है, विधान सभा की समिति में शिकायत की हुई है आज तक कार्यवाही करने की बजाय क्या मध्यप्रदेश में कोई ऐसा अधिकारी नहीं है, कोई आईएएस नहीं है जिसको हम सीईओ के पद पर आजीविका मिशन जैसे महत्वपूर्ण पद पर बिठा सकें, क्यों, क्योंकि चुनाव जिताने का उनके पास पता नहीं कौन सा आंकड़ा है और माननीय मुख्यमंत्री जी उनसे प्रभावित हो जाते हैं. आज स्थिति यह है कि दो वर्ष से स्कूल के बच्चों का गणवेश जो गरीब बच्चों के लिये शासकीय स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों का गणवेश वितरित नहीं हुआ है, सिर्फ इसी भ्रष्टाचार की वजह से और घटिया क्वालिटी के कपड़े खरीदे गये और महिलाओं को जो स्व-सहायता समूह को सिलाई करने के लिये देते हैं उनको मिला भी नहीं है बल्कि मार्केट से खरीद कर दिया जा रहा है और आज भी दो वर्षों से नहीं दिये गये हैं, इसकी जांच अगर निष्पक्ष हो जाये तो बहुत सारे लोग इसमें निपटेंगे और जो अधिकारी दोषी पाये जाते हैं जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के केस रजिस्टर्ड हैं उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं होती है, मेरे पास तो जांच रिपोर्ट भी है, माननीय अगर आप अनुमति दें तो हम इसको पटल पर भी रखने को तैयार हैं, जांच रिपोर्ट हैं जिसमें सीधे-सीधे नौकरियों की भर्ती में दोषसिद्ध हो रहा है नौकरियों की भरती में पर ऐसे अधिकारी के खिलाफ पता नहीं माननीय मुख्यमंत्री जी क्यों मेहरबान हैं, हम तो आपको ही बोलेंगे क्योंकि मुखिया आप हैं. हो सकता है आप मेहरबान न हों आपको कोई गलत जानकारी दे रहा हो विधान सभा कार्यवाही / 21 छ्रद्गष्द्वड्डद्गह्म 2022

अशोधित / प्रकाशन के लिए नहीं और जो व्यक्ति पूरी तरह से आपको आंकड़ा दे देते हैं कि इतने लाख आजीविका मिशन के मेम्बर हैं, महिलायें हैं पर सच्चाई यह है कि भारत सरकार की एक एजेंसी है जिसने जांच की थी और उसमें आधे से ज्यादा समूह फर्जी पाये गये थे वह भी हमारे पास है, जांच रिपोर्ट भी है. ऐसे भ्रष्ट अधिकारी को क्यों संरक्षण दिया जा रहा है माननीय मुख्यमंत्री महोदय, मेरा आपसे आग्रह है ऐसे अधिकारी के ऊपर तत्काल कार्यवाही होनी चाहिये और किसी सक्षम अधिकारी की नियुक्ति होना चाहिये और जो आई. ए. एस. महिला, उस बहन को हम भी जानते हैं, वह पहले हमारे पास जब हम मंत्री थे, एक बार मिली थीं आज जिस तरह से उनके साथ बदतमीजी हुई, जिस तरह से हम लोगों ने पेपरों में पढ़ा था, एक ही बार मिले हैं, हम उनको जानते नहीं है, पर जिस तरह की कार्यवाही और जिस तरह से नेहा मराव्या शायद उनका नाम है, उन पर इस तरह से अगर किसी अधिकारी के साथ, किसी बहन के साथ अगर इस तरह से कोई ईमानदारी से काम करता है और इसके साथ इस तरह का बर्ताव होता है, तो हम समझते हैं कि उचित नहीं है. माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार तो बहुत सारे नारे देती है, कभी रोजगार दिवस मनाती है, तो कभी आओ बनाये अपना मध्यप्रदेश तो कभी ग्राम उदय से भारत उदय, तो कभी आत्मनिर्भर भारत पर लाकर छोड़ दिया है और आजकल चल रहा है। मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान. माननीय मुख्यमंत्री जी, नो डॉउट व्यक्तिगत रूप से बहुत अच्छे इंसान है, बहुत अच्छे हैं. अभी तो कमल पटेल जी के यहां गये थे, हम कभी भाषण राजनीतिक सुनते थे, पर आपका हमने प्रवचन भी सुना. हम तो आपसे निवेदन करेंगे कि भविष्य में आप झांसाराम की जगह भी ले सकते हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं आप, पहले वह भी बहुत अच्छा वक्ता थे, अब उनका नाम यहां इस सदन में लेना ठीक नहीं है।

इलाज के लिए भटक रहे मरीज

संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों की हड़ताल से बदहाल हुई स्वास्थ्य सेवाएं, कई केंद्रों पर लटका है ताला

❑ बालाघाट

संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों की हड़ताल से जिले भर में स्वास्थ्य सेवा बदहाल हो गई हैं। दूर-दराज के स्वास्थ्य केंद्रों में इलाज कराने के लिए रोगी भटकते रहे, लेकिन उनका इलाज नहीं हो पाया। पिछले चार दिनों से जिले भर के करीब आठ सैकड़ा से अधिक संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी अपनी चार सूत्रीय मांगों को लेकर हड़ताल पर बैठे हुए हैं। रोगियों के परिजनों का कहना रहा कि दूर-दराज के स्वास्थ्य केंद्रों में स्थिति पूरी तरह से बद्तर हो गई हैं।

कई केंद्र तो ऐसे है, जहां पर इलाज करने वाला कोई नहीं हैं और केंद्रों पर ताले जड़े हुए हैं। इधर जिले के तहसील व ग्रामीण अंचलों में भी स्वास्थ्य सेवा पूरी तरह प्रभावित हो चुकी हैं। एक साथ आठ सैकड़ा से ज्यादा संविदा स्वास्थ्य कर्मियों के मौजूद नहीं रहने के कारण रोगियों को उपचार कराने के लिए बेहद ही मानसिक एवं आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा हैं। इधर ग्रामीण अंचलो में हड़ताल की वजह से स्वास्थ्य केंद्र बंद रहने के लिए कारण पिछले चार दिनों से उपचार कराने के लिए रोगी भटक रहे हैं। उनका कहना है कि मौसम में आए बदलाव की वजह से सर्दी खांसी के साथ ही स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर पड़ रहा हैं, लेकिन स्वास्थ्य केंद्र बंद रहने के कारण वे उपचार कराने से वंचित हो रहे है। सर्दी, खांसी, बुखार के साथ ही अन्य बीमारियों का उपचार को लेकर ग्रामीण जन मिलो का सफर तय कर जिला मुख्यालय पहुंच रहे हैं। नगर के अधिकतर निजी अस्पतालों में रोगियों की भीड़ देखने को मिल रही हैं। रविवार को जिला अस्पताल की ओपीडी बंद रहने के कारण रोगियों को निजी नर्सिंग होम की ओर ही रुख करना पड़ा। जानकारी के अनुसार हड़ताल में 831 संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी शामिल हैं। ऐसी स्थिति में करीब 250 उप स्वास्थ्य केंद्रों में उपचार नहीं हो पा रहा हैं। हड़ताल में शामिल संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों का कहना रहा कि वर्ष 2018 की नीति को लागू करने, समस्त संविदा कर्मचारियों को तत्काल नियमित किए जाने सहित अन्य मांगों को लेकर यह प्रदर्शन किया जा रहा हैं। उन्होंने कहा कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती तब तक उनका प्रदर्शन जारी रहेगा।हड़ताल की वजह से राष्ट्रीय बाल सुरक्षा कार्यक्रम अंतर्गत स्कूल के 5 से 18 साल तक के सभी बच्चों की जांच, पहचान, रेफर का कमा, टीबी रोग की जांच परीक्षण, दवा वितरण का कार्य, एएनएम के टीकाकरण, मैदानी क्षेत्र के भ्रमण का कार्य, पैथोलॉजी जांच सहित अन्य कार्य प्रभावित हो रहे हैं। वहीं टेली कंसल्टेशन, नवजात शिशुओं की देखभाल, बीपी, शुगर के मरीजों की जांच, दवा वितरण, वृद्वजनों की देखभाल, नाक कान गले की जांच, टीबी के मरीजों की जांच, निक्षय आइडी बनाना, एनसीडी पोर्टल पर कार्य, अनमोल एप पर कार्य, किशोर बालक-बालिकाओं की जांच, मलेरिया रक्त जांच, टाइफाइड जांच सहित अन्य महत्वपूर्ण जांच प्रभावित हो रही हैं।

सुशासन दिवस पर आयुष मेला आयोजन 25 दिसंबर को,रोगो का होगा उपचार

रिपोर्ट - कैलाश कुमार

शहडोल। जिला आयुष अधिकारी डॉ शशि प्रभा पांडे ने जानकारी दी है कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्व. श्री अटल बिहारी बाजपेई की जयन्ती सुशासन दिवस के अवसर पर जिला स्तरीय आयुष मेला का आयोजन आयुष विभाग जिला शहडोल द्वारा बाणगंगा मेला मैदान शहडोल में दिनांक 25.12.2022 रविवार को प्रातः 10 बजे से शाम 4 बजे तक किया जा रहा है। इस मेला में विभिन्न प्रदर्शिनी के अलावा आयुर्वेद, होम्योपैथी व योगासन द्वारा जटिल रोगो का उपचार किया जाएगा। विशेष रूप से असंचारी रोगों (डायबिटिस, आथ्राइटिस, उच्च रक्तचाप, अर्श व रक्ताल्पता) के लिए उपचार व्यवस्था होगी। ब्लड शुगर व हीमोग्लोबिन की जांच की सुविधा भी रहेगी। मेला का विशेष आर्कषण औषधीय पौधे व जीवन अमृत काढ़ा का वितरण है।

आरईएस में पदस्थ बाबू 20 हजार की रिश्वत लेते गिरफ्तार ठेकेदार की 6 लाख की राशि जारी करने मांग रहा था रिश्वत

❑ जबलपुर

जबलपुर लोकायुक्त पुलिस ने संभागीय ग्रामीण यांत्रिकी विभाग में पदस्थ सहायक बाबू ग्रेड-2 को बीस हजार रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। बाबू का नाम शंभू सिंह ठाकुर है जो कि स्टेडियम को बनाने के बाद सिवनी निवासी ठेकेदार सुरेन्द्र कुमार माल्या से रुकी राशि जारी करने के एवज में रिश्वत मांग रहा था जिसे कि गिरफ्तार कर पूछताछ की जा रही है।

जबलपुर लोकायुक्त पुलिस को सिवनी निवासी सुरेन्द्र कुमार माल्या ने बताया कि सिवनी केवलारी में उन्होंने खेल स्टेडियम 30 लाख रुपए में बनाया था जिसको हेण्ड ओवर 2021 में कर दिया था। स्टेडियम बनाने के बाद संभागीय ग्रामीण यांत्रिकी विभाग से ठेकेदार सुरेन्द्र कुमार माल्या को बची हुई 6 लाख रुपए की राशि और लेना था जिसको जारी करने के लिए बाबू शंभू सिंह ठाकुर 40 हजार रुपए की डिमांड ठेकेदार से कर रहा था। जिसकी शिकायत सुरेन्द्र कुमार ने जबलपुर लोकायुक्त से की थी। ठेकेदार सुरेंद्र कुमार माल्या की शिकायत को जबलपुर लोकायुक्त ने जांच कर सही पाए और फिर आज दोपहर ग्रामीण यांत्रिकी विभाग में पदस्थ बाबू जब 20000 रुपए ले रहा था, उसी दौरान जबलपुर लोकायुक्त पुलिस ने उसे रंगे हाथों गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि शंभू सिंह ठाकुर की 40 साल की नौकरी हो चुकी है जबकि उसके रिटायरमेंट को 3 साल और बचे है । जबलपुर लोकायुक्त पुलिस की कार्यवाही से ग्रामीण यांत्रिकी विभाग में हड़कंप मच गया है।

नियमितीकरण की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे संविदाकर्मी

❑ दमोह

दमोह में जिले भर के संविदा स्वास्थ्यकर्मी अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं। उनकी मांग है कि जब तक उन्हें नियमित नहीं किया जाता वह अपना धरना समाप्त नहीं करेंगे। सोमवार को कलेक्ट्रेट के सामने धरना स्थल पर मौजूद सभी संविदा स्वास्थ्य कर्मियों ने अपना विरोध जताते हुए मानव श्रृंखला बनाई और मुख्यमंत्री को यह संदेश देने का प्रयास किया कि उनकी मांगें जायज है, जिन्हें तत्काल पूरा किया जाए। संविदा स्वास्थ्य कर्मियों का कहना है कि कोविड जैसे कठिन समय में उन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर लोगों की सेवा की है। सरकार कई बार उन्हें आश्वासन दे चुकी है, लेकिन अब उनकी मांग है कि मुख्यमंत्री उनकी इस मांग को पूरा करें। उनका कहना है कि उनका आर्थिक संकट तभी समाप्त होगा। जब उन्हें नियमित किया जाए और जबतक उनकी मांग पूरी नहीं होती। आंदोलन जारी रखेंगे और दिनों दिन इस आंदोलन को उग्र रूप देते जाएंगे।

रोटरी क्लब ऑफ वैनगंगा दिवास ने कराई 400 छात्राओं की जांच

❑ बालाघाट

बालाघाट में सामाजिक सेवा में अग्रणी रोटरी क्लब ऑफ वैनगंगा दिवास संगठन ने अपने सामाजिक दायित्व को निभाते हुए नगर के उत्कृष्ट विद्यालय में छात्राओं की स्वास्थ्य जांच के लिए शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में बतौर अतिथि भाजपा जिला महामंत्री मौसम हरिनखेड़े, शांता तिवारी और समाजसेवी कृष्णा सचदेव प्रमुख रूप से उपस्थित रही। परंपरानुसार शिविर का शुभारंभ मां सरस्वती के छायाचित्र पर माल्यार्पण के साथ किया गया। जिसके उपरांत अतिथि देवो भव: के भाव के साथ दिवास संगठन अध्यक्ष रोटे. श्रुति तिवारी व सचिव रोटे. गीता सचदेव की ओर से स्वागत किया गया। स्वास्थ्य शिविर में विद्यालय की लगभग 400 छात्राओं के हीमोग्लोबिन, सिकल सेल एनिमिया और थायराइड की जांच की गई।

गंगा-जमुनी तहजीब की अद्भुत परंपरा के साथ तानसेन समारोह शुरू

❑ ग्वालियर

सुरों के सरताज कहे जाने वाले तानसेन की याद में ग्वालियर में 19 दिसंबर से तानसेन समारोह का आगाज हो गया है। परम्परागत तरीके से शुरू हुए इस समारोह में सबसे पहले समधि स्थल पर हरिकथा और मिलाद का आयोजन किया गया। इसके बाद शाम को मशहूर बांसुरी वादक पं. नित्यानंद हल्दीकर को तानसेन अलंकरण और मुंबई की सामवेद सोसाइटी को राजा मानसिंह तोमर राष्ट्रीय सम्मान दिया जाएगा।

ग्वालियर में विश्व संगीत तानसेन समारोह की महफिल सज चुकी है। हर कोई बस तानसेन की समधि पर आकर तानसेन के रंग में रंगने की कोशिश में लग गया है। हिंदू हो या मुस्लिम सभी उन्हें अपने-अपने तरीके से श्रद्धांजलि देने की कोशिश में लगे हैं। सबसे पहले ढ़ोली बुआ महाराज के शिष्यों ने तानसेन की समधि पर श्रद्धांजलि दी, तो वहीं मुस्लिम समाज की ओर से उनके लिए मिलाद शरीफ का आयोजन किया गया। ऐसे में रासिकों के पहुंचने का भी

सिलसिला शुरू हो गया है। तानसेन समारोह को लेकर दूर-दराज से लोगों के पहुंचने का सिलसिला भी जारी है। कुछ रसिक प्रेमी तो ऐसे भी जो अपनी पैदाईश के बाद से ही तानसेन समारोह को देखने और सुनने आ रहे हैं। लेकिन इस बार देश के कलाकारों के साथ कुछ तानसेन प्रेमी भी समारोह अपनी प्रस्तुति देंगे। जिसको लेकर रासिक उत्साहित हैं। उनके मुताबिक तानसेन समारोह में गंगा-जमुनी तहजीब दिखाई देती है। भारतीय शास्त्रीय संगीत की अनादि परंपरा के श्रेष्ठ कला मनीषी तानसेन की स्मृति में ग्वालियर में आयोजित होने वाले तानसेन समारोह का इस साल 98वाँ आयोजन हो रहा है।

संपादकीय

स्टिवन स्पीलबर्ग- जिनके फिल्मांकन में नजर आती है असामान्य खोज

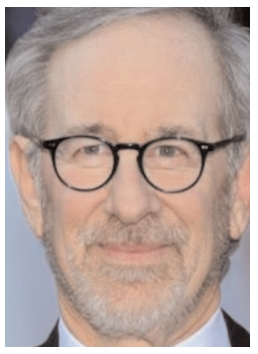

एक ऐसा निर्देशक जिसकी अधिकांश फ़िल्मों की थीम सामान्य लोगों के द्वारा असामान्य की खोज है, ये असामान्य चीजें कोई स्थान हो सकता है, कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई जीव हो सकता है अथवा कोई वस्तु हो सकती है। इस निर्देशक की एक और विशेषता है इसकी फ़िल्मों के प्रमुख पात्र अक्सर टूटे-बिखरे परिवार से आते हैं, इन परिवारों में माता-पिता का तलाक हो चुका होता है, पिता या तो गायब होता है या फ़िर हिचकिहाट लिए, गैरजिम्मेदार व्यक्ति होता है। असल में यह निर्देशक का अपना अनुभव है, उसके माता-पिता का तलाक हुआ था। इस अमेरिकी निर्देशक की कुछ फ़िल्मों के नाम हैं, 'ई.टी. दि एक्स्ट्रा-टेरेस्ट्रियल', 'जॉज', 'एम्पायर ऑफ़ द सन', 'द कलर पर्पल', 'वेस्टसाइड स्टोरी', 'एमिस्टाड',

'लिंकन', 'वार ऑफ़ द वर्ल्ड्स', 'माइनोरिटी रिपोर्ट', 'ए. आई. आर्टिफ़िसियल इंटेलिजेंस', 'सेविंग प्राइवेट राइन', 'सिंडलर'स लिस्ट', 'जोरासिक पार्क'...ओह लिस्ट समाप्त ही नहीं हो रही है। अब तक 160 से ऊपर फिल्में प्रड्यूस करने वाले और 58 फ़िल्मों का निर्देशन करने वाले, 3 ऑस्कर पुरस्कार (1998 में 'सेविंग प्राइवेट राइन' तथा 1994 में 'सिंडलर'स लिस्ट' के सर्वोत्तम निर्देशक तथा 'सिंडलर'स लिस्ट' सर्वोत्तम पिक्चर का साझा पुरस्कार) जीतने वाले इस प्रसिद्ध अमेरिकी का नाम है स्टिवन स्पीलबर्ग। और अभी काम जारी है। 1987 में अकादमी ने उन्हें स्पेशल ऑनर दिया है। सिने-इतिहास का एक सबसे प्रभावशाली, प्रेरक और धनी स्टिवन एलन स्पिलबर्ग 18 दिसम्बर 1946 को ओहायो के सिनसिनाटी में पैदा हुआ था। मां कॉन्सर्ट में पियानो वादक तथा रेस्तरां की मालकिन थी और पिता इलेट्रिकल इंजीनियर। पति-पत्नी दोनों रूस से आकर अमेरिका में बसे यहूदी थे। शायद यही कारण है बेटे ने होलोकास्ट से जुड़ी कई फ़िल्म बनाई तथा टॉम हैंक्स के साथ मिल कर द्वितीय विश्वयुद्ध पर 'सूटिंग वार-वर्ल्ड वार द्वद्व कॉम्बैट कैमरामेन' डॉक्यूमेंट्री बनाई और उसी साल 2000 में होलोकास्ट पर एक और डॉक्यूमेंट्री 'आईज ऑफ़ द होलोकास्ट' प्रड्यूस की। स्टिवन ने कैलिफोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटी लॉन्ग बीच में पढ़ाई शुरू की लेकिन बीच में पढ़ाई छोड़ कर फ़िल्मों से जुड़ गए। शुरू में कुछ शॉर्ट फिल्में बनाई, 'बैटल ग्राउंड' में द्वितीय विश्वयुद्ध के फ़ुटेज का उपयोग किया गया है। 1961 में 'इस्केप टू नोव्हेयर' में द्वितीय विश्वयुद्ध में बच्चों को सैनिक के रूप में प्रस्तुत किया गया है। 'फ़ायरलाइट' का निर्देशन उनकी भविष्य की कई फ़िल्मों की दिशा-दशा तय कर देता है, इसमें एक कस्बे पर एलियन्स आक्रमण करते हैं। उन्होंने 'एम्बलिन' बनाई जिसमें रेगिस्तान की प्रमुखता है, यह भी भविष्य की फ़िल्मों का संकेत था। कभी कॉफ़ी न चखने वाले स्टिवन स्पिलबर्ग '007' मूवी के प्रशंसक हैं।

कई देशों में हो रहे विरोध प्रदर्शन दर्शा रहे हैं कि तानाशाही से जनता को दबाया नहीं जा सकता

इन देशों के नागरिक अपनी तकलीफों और मानवाधिकारों को लेकर लंबे अर्से से कसमसा रहे हैं। कठोर कानून और निर्दयी शासन तंत्र के खौफ के बावजूद नागरिकों ने सड़कों पर उतर कर प्रदर्शन करने का दुस्साहस दिखाया। हालांकि ईरान और चीन की कोशिश यही रही है कि अपने देश के नागरिकों पर चलाए गए दमन चक्र की सूचनाएं किसी भी तरह से देश से बाहर नहीं जाए, ताकि विश्वव्यापी बदनामी से बच सकें। इन देशों से आ रही सूचनाओं से जाहिर है कि मौजूदा शासन तंत्र से आजिज आ चुके लोगों ने मौत और सजा के भय के बावजूद सड़कों पर प्रदर्शन कर सरकारों का जम कर विरोध किया।

दार्शनिक और वैज्ञानिक अनुसंधान के प्रवर्तक नोबेल पुरुस्कार विजेता नील्स बोर का कथन के मुताबिक तानाशाही का सबसे जोरदार हथियार है गोपनीयता, लेकिन लोकतंत्र का सबसे असरदार हथियार है खुलापन। ईरान, चीन, म्यांमार, थाइलैंड और सूडान में हुए विरोध प्रदर्शन इस बात का प्रमाण हैं कि सूचनाओं के जरिए ई विलेज बनती दुनिया में कठोर कानून या तानाशाही से आम अवाम की आवाज को दबाया नहीं जा सकता। ये सभी देश नागरिक अधिकारों के उत्पीड़न के लिए बदनाम हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल की वर्ष 2021 की रिपोर्ट के मुताबिक फांसी देने के मामले में चीन और ईरान दुनियां के शीर्ष देश हैं। चीन ने करीब एक हजार और ईरान ने करीब 314 लोगों को फांसी दी गई।

इन देशों में लोगों के खिलाफ किए जा रहे उत्पीड़न से यह भी साबित होता है कि बदले हुए हालात में बंदूकों की नोंक पर लंबी अवधि तक मानवाधिकारों को राष्टीय एकता-अखंडता, संस्कृति या धर्म के नाम पर दबाया नहीं जा सकता। यही वजह रही आखिरकार ईरान और चीन जैसे कट्टर देशों की सरकार ने भारी खून-खराबे के बाद आंदोलनकारियों के आक्रोश के सामने झुकते हुए उनकी मांगे मंजूर कर ली। इन देशों में सरकार के खिलाफ बोलने, संस्कृति और धर्म के नाम पर फांसी की सजा दिया जाना आम बात है। किन्तु इस बार हुए अपनी मांगों को लेकर आंदोलन करने वाले लोगों को जेल या फांसी का डर भी नहीं डरा सका। ईरान ने भारी दबाव में आकर मोरैलिटी पुलिस को भंग कर दिया। इसी तरह चीन भी 70 सालों में पहली बार आंदोलनकारियों के सामने झुकते हुए कोविड में प्रतिबंधों में छूट देने के लिए सहमत हो गया। गौरतलब है कि ईरान में इस्लाम से जुड़े नियमों जैसे कि हिजाब, बुर्का आदि का पालन कराने के लिए मोरैलिटी पुलिस बनाई गई। इसका गठन पूर्व मेहमूदक अहमदीनेजाद के समय में किया गया था जो ईरान के एक कट्टरपंथी नेता और राष्टपति के तौर पर जाने जाते हैं। उस दौर में इसका काम हिजाब की संस्कृति को बढ़ाने का था। सफेद और हरे रंग की वैन से चलने वाली इस पुलिस के कर्मचारी कहीं पर भी महिलाओं को टोकते दिख जाते। कई बार इस रोक-टोक ने हिंसक का रूप ले लिया। ऐसे कई मामले सामने आए हैं, जब महिलाओं को उनके हिजाब को लेकर सरेआम बुरी तरह मारा-पीटा गया। जेलों में बंद करके लोगों को यंत्रणाएं दी गई। ऐसा ही मामला बुर्के से चेहरा नहीं ढकने वाली महसा अमीनी का था। अमीनी की मौत से भड़की आक्रोश की चिंगारी ने दावानल का रूप धारण कर लिया। विरोध का यह मुद्दा न सिर्फ ईरान में बल्कि पूरे विश्व में फैल गया। कई देशों की महिलाओं और हस्तियों ने सार्वजनिक तौर पर बाल कटवा कर ईरान का विरोध किया। ईरान ने इस आंदोलन को दबाने के लिए हर तरह के हथकंडों का इस्तेमाल किया। हजारों लोगों के खिलाफ मुकदमें दर्ज किए गए। प्रदर्शनकारियों पर गोलियां बरसाई गई। ईरान में सुरक्षा बलों के हाथों करीब 380 प्रदर्शनकारी मारे गए। मृतकों में 47 बच्चे भी शामिल हैं।

इन देशों के नागरिक अपनी तकलीफों और मानवाधिकारों को लेकर लंबे अर्से से कसमसा रहे हैं। कठोर कानून और निर्दयी शासन तंत्र के खौफ के बावजूद नागरिकों ने सड़कों पर उतर कर प्रदर्शन करने का दुस्साहस दिखाया। हालांकि ईरान और चीन की कोशिश यही रही है कि अपने देश के नागरिकों पर चलाए गए दमन चक्र की सूचनाएं किसी भी तरह से देश से बाहर नहीं जाए, ताकि विश्वव्यापी बदनामी से बच सकें। इन देशों से आ रही सूचनाओं से जाहिर है कि मौजूदा शासन तंत्र से आजिज आ चुके लोगों ने मौत और सजा के भय के बावजूद सड़कों पर प्रदर्शन कर सरकारों का जम कर विरोध किया।

ईरान की तरह चीन ने भी पहले कोविड प्रतिबंधों के खिलाफ सड़कों पर उतरे चीनी नागरिकों पर कानून की आड़ में पुलिस और सैन्य बलों का इस्तेमाल किया, किन्तु लंबे समय तक चीन भी अपने नागरिकों की आवाज को दबाने में सफल नहीं हो सका। चीन में कोरोना के मामले बीते दिनों तेजी से बढ़े और सरकार ने अपनी जीरो कोविड पॉलिसी को पूरे देश में सख्ती से लागू किया। सख्त प्रतिबंधों के कारण लोगों की आजीविका प्रभावित हो रही थी और यही कारण है कि पूरे चीन में व्यापक विरोध प्रदर्शन हुए। प्रदर्शन की यह आग शंघाई से लेकर बीजिंग और वुहान से शिनजियांग तक फैल गई। इतना ही नहीं प्रदर्शनकारियों ने राष्टपति शी जिनपिंग का भी विरोध किया। लोगों ने नारे लगाते हुए चीन की सत्तारुढ़ कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीसी) से सत्ता छोड़ने की मांग की। इसी तरह सूडान की सेना ने प्रधानमंत्री अब्दल्लाह हमदोक समेत कई नेताओं को गिरफ्तार कर इमरजेंसी घोषित कर दी। इसके बाद से सड़कों पर लोगों का विरोध प्रदर्शन पर उतर आए। लोगों पर सैनिकों ने गोलियां भी दागीं जिसमें 10 लोगों के मारे जाने और कई अन्य के घायल हो गए। म्यांमार की सेना ने अपने ही लोगों पर एयर स्ट्राइक कर आतंक फैला दिया। हवाई हमलों में 80 से ज्यादा लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। घटना स्थल पर सैन्य विमान की ओर से 4 बम गिराए गए थे। म्यांमार की सेना पिछले साल आंग सान सू ची की निर्वाचित सरकार का तख्तापलट करने के बाद से हजारों लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। इसके अलावा उस पर 2,300 से अधिक आम नागरिकों की हत्या का आरोप भी लगा है। थाइलैंड में भी हालात कुछ दूसरे देशों की तरह ही हैं। धरना और विरोध पर यहां भी सख्त पाबंदी है। सेना द्वारा 2014 के तख्तापलट में चयनित सरकार को अपदस्थ किए जाने के बाद से थाइलैंड में पहली बार 2019 में चुनाव हुए पर आम नागरिकों को अभी अपने अधिकारों की मांग करने की छूट नहीं है।बैंकाक में सरकार ने पांच से अधिक लोगों के एक साथ खड़े होने पर रोक लगाई हुई है। ऐसे प्रतिबंधों को असली मकसद अवाम की आवाज को दबाना ही रहा है। दलील यह दी गई कि प्रतिबंध राष्टीय सुरक्षा पर खतरे की वजह से लगाए गए हैं। एक छात्र नेता के आह्वान पर बैंकॉक की जनता सड़कों पर ही उतर आई। प्रदर्शनकारियों ने देश के राजा महा वजीरालोंगकोर्न के साथ ही प्रधानमंत्री प्रयुत चन ओचा के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और प्रधानमंत्री से गद्दी छोड़ने की मांग की। ईरान और चीन की निरंकुश सरकारों का आंदोलनकारियों के सामने झुकना यह दर्शाता है कि वह दिन दूर नहीं है, जब लोकतंत्र की बयार को रोकना इन देशों में नामुमकिन हो जाएगा। आहिस्ता से ही सही लोकतंत्र का बसंत इन देशों में पूरी रंगत से आएगा जरूर। इसकी पदचाप नागरिक अधिकारों विरोधी इन देशों में सुनाई पड़ रही है। लोकतंत्र की यह कवायद भारी जनांदोलनों के जरिए इन देशों की कट्टरपंथियों और तानाशाहों को संपूर्ण आजादी बहाल करने को मजबूर कर देंगे, किन्तु यह भी निश्चित है कि यह रास्ता कांटों भरा है और बगैर कुर्बानी के तय नहीं होगा।

-योगेन्द्र योगी

महिला सशिक्तकरण की बात तो बहुत होती है पर प्रतिनिधित्व की स्थिति दयनीय क्यों है?

आज़ादी का अमृत महोत्सव मना चुके राष्ट्र में विधायी संस्थानों लोकसभा एवं विधानसभाओं में महिला प्रतिनिधियों की संख्या दयनीय है, नगण्य है। 75 वर्षों में लोकसभा में महिलाओं का प्रतिनिधित्व 10 प्रतिशत तक भी नहीं बढ़ा है जबकि विधानसभाओं में यह स्थिति और भी चिन्तनीय है, वहां 9 प्रतिशत ही महिला प्रतिनिधि है। इस बार हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव नतीजों के बाद यह मुद्दा फिर सुर्खियों में है कि वहां अड़सठ सदस्यीय विधानसभा में सिर्फ एक महिला विधायक होगी। हालांकि इस बार के चुनाव में वहां अलग-अलग दलों की ओर से कुल चौबीस महिला प्रत्याशी थीं।

मुख्यधारा की राजनीति में महिलाओं का प्रतिनिधित्व क्यों नहीं बढ़ रहा है, क्यों राजनीतिक दल महिलाओं को प्रतिनिधित्व देने के नाम पर उदासीन है? आखिर क्या वजह है कि जब संसद में बिना बहस के भी कई विधेयक पारित हो जाते हैं, तब भी संसद और विधानसभाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व कानूनी तौर पर सुनिश्चित कराने को लेकर राजनीतिक पार्टियां गंभीर नहीं दिखती हैं? दुनिया का सबसे बड़ा एवं सशक्त लोकतंत्र होने का दावा करने वाला भारत महिलाओं के प्रतिनिधित्व के नाम पर ईमानदारी नहीं दिखा पा रहा है। चिन्तनीय पहलू है कि चुनावी प्रतिनिधित्व के मामले में भारत, अंतर-संसदीय संघ की संसद में महिला प्रतिनिधियों की संख्या के मामले में वैश्विक रैंकिंग में कई स्थान नीचे आ गया है, जिसमें वर्ष 2014 के 117वें स्थान से गिरकर जनवरी 2020 तक 143वें स्थान पर आ गया। इस बार के गुजरात एवं हिमाचल प्रदेश के चुनाव में महिला प्रतिनिधित्व के लिहाज से देखें तो स्थिति और दयनीय हुई है। गुजरात में भी पिछले विधानसभा चुनाव में तेरह के मुकाबले इस बार सिर्फ दो महिला प्रतिनिधियों की बढ़ोतरी हुई। जबकि वहां विधानसभा की कुल क्षमता एक सौ बयासी विधायकों की है और इस बार कुल एक सौ उनतालीस महिलाएं चुनाव के मैदान में थीं। अमेरिका में राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ चुकीं हिलेरी क्लिंटन का कहना है, जब तक महिलाओं की आवाज़ नहीं सुनी जाएगी तब तक सच्चा लोकतंत्र नहीं आ सकता। जब तक महिलाओं को अवसर नहीं दिया जाता, तब तक सच्चा लोकतंत्र नहीं हो सकता। आदर्श एवं सशक्त लोकतंत्र के लिये महिला प्रतिनिधित्व पर गंभीर चिन्तन एवं ठोस कार्रवाई जरूरी है। भारत में महिलाएँ देश की आबादी का लगभग आधा हिस्सा हैं। यूँ तो यह आधी आबादी कभी शोषण तो कभी अत्याचार के मामलों को लेकर अक्सर चर्चा में रहती है।

कोरोना से चीन का हाल बेहाल, तेजी से चीनियों को निबटाने में लगा है Xi Ka Virus

चीन में विरोध प्रदर्शन बढ़ने से परेशान वहां की सरकार ने जीरो कोविड नीति में छूट तो दे दी लेकिन उसके बाद कोरोना के मामले जिस तेजी से बढ़े हैं उससे देश के हालात को संभालना राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बलबूते से बाहर होता जा रहा है। शी जिनपिंग ने जो वायरस दुनिया को निबटाने के लिए बनवाया था वही वायरस अब उनको ही निबटाने में लगा हुआ है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए चीनी अर्थव्यवस्था को झटके पर झटके लग रहे हैं क्योंकि कारोबार बंद है, ऑफिसों में ताले लग गये हैं, देश में निवेश आना भी बंद हो गया है, वायरस आ जाने के डर से दुनिया के अन्य देश चीनी माल खरीदने से कतराने लगे हैं जिससे हवाई अड्डों और बंदरगाहों पर तरह तरह के सामान से भरे कंटेनरों का अंबार लगा हुआ है और उसके अंदर रखा माल सड़ रहा है। इस बीच, इस प्रकार की भी खबर है कि विशेषज्ञों ने चीन में कोरोना वायरस की नई लहर के चलते 10 लाख लोगों की मौत का अनुमान जताया है। चीन की सरकार हालांकि अपने देश में कोरोना के मार की सही तस्वीर बाहर नहीं आने दे रही है लेकिन फिर भी सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल हो रहे हैं

उनमें दिख रहा है कि राजधानी बीजिंग में कई अस्पतालों और क्लीनिकों में मरीजों की भीड़ लगी हुई है और मरीजों की लाइन फुटपाथ तक पहुँची हुई है। बीजिंग में कड़ाके की ठंड है लेकिन लोग बाहर खड़े अपनी बारी आने का इंतजार करने को मजबूर हैं। कुछ ऐसे भी वीडियो वायरल हो रहे हैं जिसमें अस्पतालों के बाहर लोग अपनी कारों में बैठे अपनी बारी का इंतजार करते दिख रहे हैं। बताया जा रहा है कि जिनको ज्यादा बुखार है उनको अस्पतालों के बाहर ही बैठने को कहा जा रहा है। इस प्रकार की रिपोर्टें हैं कि चीन में अधिकांश इलाकों में कोरोना के ओमीक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है और प्रशासन से जुड़े लोगों ने भी सुविधाएं और सेवाएं मुहैया कराने के मामले में हार मान ली है जिससे लोग हैरान-परेशान हैं।

किसानों के कल्याण और उन्नति के लिए चलाई जा रही हैं अनेक योजनाएं : स्वास्थ्य मंत्री डॉ चौधरी

❑ रायसेन

सांची स्थित शासकीय नर्सरी में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि स्वास्थ्य मंत्री डॉ प्रभुराम चौधरी द्वारा किसानों को सब्जी किट निशुल्क वितरित की गई। प्रत्येक किसान को वितरित की गई 10-10 हजार रुपए मूल्य की सब्जी किट में 0.200 हैक्टेयर के लिए हाइब्रिड टमाटर बीज 200 ग्राम, प्लास्टिक क्रेट 5 नग, शेडनेट छाया हेतु 60 वर्ग मीटर हजारा, सिंचाई हेतु एक नग बैटरी चलित स्प्रे पंप शामिल है।

इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री डॉ चौधरी ने कहा कि सरकार द्वारा किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए अनेक प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही हैं। किसानों को उद्यानिकी की खेती का प्रशिक्षण दिया जा रहा है द्य साथ ही उन्नत किस्म के बीज, खाद सहित कृषि यंत्रों की खरीद पर अनुदान राशि भी प्रदान की जाती है। किसान कम रकबे में भी उद्यानिकी खेती अपनाकर अधिक से अधिक लाभ कमा सकते है। उन्होंने किसानों से पात्रतानुसार अधिक से अधिक योजनाओ का लाभ लेने के लिए कहा। सहायक संचालक उद्यानिकी श्री एनएस तोमर द्वारा जानकारी दी गई कि शासन की योजना के तहत खाद्य प्रसंस्करण उद्योग लगाने के लिए कुल परियोजना लागत का 35त्न अनुदान अधिकतम ?1000000 तक की अनुदान राशि दी जाती है। इसमें हितग्राही चावल मिल, दाल मिल, पोहा मिल, बेकरी यूनिट, मसाला यूनिट, तेल मिल, नमकीन यूनिट, पापड़ यूनिट, अन्य सभी प्रकार के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग लगा सकते हैं। सिंचाई लाइन एवं ड्रिप सिंचाई पर लघु एवं सीमांत किसानों को 55त्न अनुदान तथा बड़े किसानों को 45त्न अनुदान की पात्रता है। उन्होंने किसानों के लिए चलाई जा रही अन्य योजनाओं की भी जानकारी दी। इस अवसर पर स्थानीय जनप्रतिनिधि, अधिकारी और बड़ी संख्या में किसान उपस्थित थे।

स्कूल संचालकों ने आरटीई राशि बढ़ाने सहित अपनी मांगों को लेकर आग्रह पत्र सौंपा

❑ मंडीदीप

मध्यप्रदेश के सभी अशासकीय विद्यालयों के संचालकों का प्रादेशिक महा अधिवेशन नगर में आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता विधायक सुरेंद्र पटवा ने की है। साथ ही स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी, पूर्व राज्य शिक्षा मंत्री दीपक जोशी उपस्थित रहे। इस महा अधिवेशन में प्रदेश के 52 जिलों से अशासकीय विद्यालयों के लगभग 3 हजार संचालक शामिल हुए। इस महा अधिवेशन में प्रदेश के सभी स्कूल के संचालकों ने शाला संचालन में होने वाली समस्याओं को एक दूसरे से आपस में साझा किया। स्कूल संचालन में आने वाली समस्याओं का आपस में परिचर्चा कर समाधान के लिए मंथन किया। कार्यक्रम में इन समस्याओं को शासन और प्रशासन स्तर पर आपसी सामंजस्य से सामने रखकर उन समस्याओं के निदान के लिए आग्रह पत्र सौपा। विशिष्ट अतिथि पूर्व शिक्षा मंत्री दीपक जोशी ने कहा कि स्कूल बसों को एंबुलेंस की तरह शुल्क माफ किया जा सकता है। स्वास्थ्य के लिए रस्सी कूद अनिवार्य करें। महंगे खेलों के स्थान पर अपने और सस्ते खेलों से जोड़ा जाए। बच्चों को सप्ताह में एक दिन कृषि कार्यों से जोड़ें जिससे बच्चे अपने क्षेत्र में ही रोजगार से जुड़ सकें।उन्होंने कहा हिंदी माध्यम को बढ़ाकर मात्र भाषा को बढ़ावा दें। प्रभुराम चौधरी ने कहा- बच्चों के माध्यम से हमारे देश का भविष्य तय होगा। मुख्यमंत्री ने शिक्षा नीति में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, रोजगारोन्मुखी शिक्षा, सांस्कृतिक शिक्षा आदि के माध्यम से प्रदेश का सर्वांगीण विकास की संकल्पना पूर्ण होगी। प्रत्येक शिक्षक का संकल्प बच्चों का विकास करना रहा है। सुरेंद्र पटवा ने कहा-भोजपुर के प्रकृतिक स्थलों की जानकारी साझा की। कहा नई शिक्षा नीति में 350 करोड़ का प्रावधान किया गया है। जिसमें 253 करोड़ शाला भवन, पुस्तकालय विकास का बजट रखा है। प्रतिनिधि मंडल को मुख्यमंत्री से मिलने का सुझाव दिया। वहीं, नपाध्यक्ष प्रियंका अग्रवाल ने कहा कोविड के बाद मोबाइल से दी जा रही शिक्षा से बच्चों में चिड़चिड़ापन आया है। उसे दूर करने का प्रयास करें। इस अवसर पर सोपास के दीपक सिंह राजपूत,प्रदेश अध्यक्ष आशीष चटर्जी, डॉ. आरके श्रीवास्तव, प्रमोद सिंह राजपूत, शिवप्रसाद जायसवाल, जिलाध्यक्ष राजेश राजोरिया, कार्यक्रम संयोजक देवी अजमेरा, सुनील खम्बरा, शेरसिंह चौहान, कपिल राजपूत, संजय मगरदे सहित प्रदेश के पदाधिकारी संस्था संचालक उपस्थित रहे। सोसायटी फ़ॉर प्रायवेट स्कूल (सोपास) के संस्थापक अध्यक्ष दीपक सिंह राजपूत ने बताया मध्य प्रदेश राज्य के सभी 52 जिलों के अशासकीय स्कूलों का सबसे बड़ा संगठन है। जिसके पूरे प्रदेश में लगभग 20 हजार संचालक हैं। जोकि प्रदेश भर में अशासकीय स्कूलों के हितार्थ में कार्य करता है। इसमें 5 लाख शिक्षक,1 करोड़ विद्यार्थियों को शिक्षा दे रहे हैं। संगठन का उद्देश्य पूर्ण क्वालिटी एजुकेशन लाना है। 80 फीसदी ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित स्कूल संचालकों को जिला स्तर पर प्रशिक्षण दिया जाएगा। पहली से 12 तक की मान्यता नवीनीकरण जो प्रति 3 वर्ष में कई जाती है उसे एक बार में 5 वर्ष के लिए करते हुए भवन अनुज्ञा के में लीज के स्थान पर किरायानामा मान- किया जाए। आरटीई में स्कूलों को दी जाने वाली फीस 20 हाजर रुपए की जाए। आईटी प्रपोजल में समय कम मिलता है अत: भौतिक सत्यापन कर 2016 से आज तक 45 हजार छात्रों की रुकी फीस प्रतिपूर्ति की जाए। 9वीं और 12 कि शिक्षा बोर्ड अलग अलग मान्यता शुल्क लेता है वह एक साथ ली जाए। स्कूल वाहनों को स्थायी परमिट दिया जाए साथ ही नवीनीकरण शुल्क ऑनलाइन प्रति वर्ष ली जाए।

मांगो के समर्थन में संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी पहुंचे भगवान गणेश व हनुमानजी की शरण में

❑ विदिशा

संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों की हड़ताल चौथे दिन भी जारी रही। रविवार के दिन भी जिले भर से स्वास्थ्य कर्मचारी हड़ताल में शामिल होने के लिए धरना प्रदर्शन स्थल पर पहुंचे। इस हड़ताल से स्वास्थ्य विभाग की मैदानी स्वास्थ सेवाएं बुरी तरह प्रभावित हो रही है। रविवार को जिला अस्पताल के मुख्य गेट के बाहर धरना स्थल पर मौजूद कर्मचारियों ने बाढ़ वाले गणेश मंदिर और रंगई स्थित हनुमान मंदिर पर पहुंचकर भगवान को अपने ज्ञापन अर्पित किए। भगवान को ज्ञापन अर्पित कर स्वास्थ्य कर्मचारियों ने सरकार को सद्बुद्धि देने की प्रार्थना की। बाढ़ वाले गणेश मंदिर पर ज्ञापन देने से पहले स्वास्थ्य कर्मचारियों को यहां मौजूद पुलिसकर्मी ने रोकने की कोशिश भी की थी। संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के जिलाध्यक्ष पंकज द्विवेदी ने बताया कि जिले में 600 से अधिक संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी हड़ताल पर चल रहे हैं। आश्वासन के बावजूद संविदा कर्मचारियों की मांग पर अब तक अमल नहीं हुआ है। प्रमुख मांगों में संविदा कर्मचारियों का नियमितिकरण, 5 जून 2018 की संविदा नीति लागू करने, पद समाप्त कर निकाले गए कर्मचारियों की बहाली करने आदि शामिल हैं। हड़ताल के चौथे दिन धरना सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक चला। इस दौरान जोरदार नारेबाजी करते हुए स्वास्थ कर्मचारियों ने अपनी मांग पर आवाज बुलंद की। इस प्रदर्शन में जिले से कई सीएचओ, स्टॉफ नर्स, चिकित्सक आदि संविदा कर्मचारी शामिल हुए। संगठन के अध्यक्ष पंकज द्विवेदी ने बताया कि कई जगहों पर सीएचओ भी रोकने के लिए विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने दबाव भी बनाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इस हड़ताल की वजह से जिले भर में स्वास्थ्य सेवाएं बुरी तरह प्रभावित हो रही हैं। सरकार को जल्द से जल्द संविदा कर्मचारियों के जायज मांगों पर अमल करना चाहिए।

मौसम का बदला पारा उत्तर से चलेगी हवाएं और रात में छाएगा घना कोहरा

❑ सीहोर

सीहोर जिले में मौसम का मिजाज लगातार उतार-चढ़ाव भरा बना हुआ है। एक बार फिर न्यूनतम तापमान में गिरावट होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। हवा की गति भी कम होगी और रात के समय घना कोहरा छाने लगेगा। जानकारी के अनुसार सीहोर जिले में इस साल मई-जून में भीषण गर्मी देखने को मिली थी और अधिकतम तापमान 44 डिग्री तक रिकार्ड हुआ था। इसके बाद जब बारिश का दौर शुरू हुआ तो जिले में 1993 एमएम बारिश दर्ज की गई और अब ठंड का मौसम आते ही ऐसा माना जा रहा था कि गर्मी बरसात के बाद ठंड भी रिकार्ड पड़ेगी, लेकिन अभी तक ऐसा हुआ नहीं है। जैसा की देखा गया पिछले 72 घंटे में आसमान में मध्यम बादल छाए रहे। हवा की दिशा पूर्व से रही जिसके कारण दिन और रात के तापमान में मामूली बढ़ोतरी रही। दिन में 26 डिग्री तक अधिकतम तापमान दर्ज हुआ, जबकि रात में 15 डिग्री तापमान रहा। बीते 24 घंटे में न्यूनतम तापमान 11 डिग्री और अधिकतम तापमान 25.5 दर्ज हुआ। मौसम को लेकर शासकीय कृषि कॉलेज के मौसम वैज्ञानिक डॉ. एसएस तोमर ने बताया कि अब आसमान में हल्के बादल से मध्यम हल्के बादलयुक्त मौसम रहने का अनुमान है। हवाओं की दिशा उत्तर पर्व से एवं पूर्व से रहेगी। हवा की गति 7 किमी प्रति घंटे रह सकती है। दिन के तापमान में बढ़ोत्तरी और रात्रि के तापमान में गिरावट होगी। इस दौरान बारिश का अनुमान नहीं है। आज से रात में घना कोहरा छाने की पूरी संभावना है। बताया गया है कि बादल युक्त मौसम रहने के कारण मटर-मसूर व चने में रोग की संभावना रहती है। नियंत्रण के लिए कार्बेन्डाजिम का छिड़काव करें। यदि बारिश होती है तो यह रोग अपने आप समाप्त हो जाता है। गेहूं फसल में कहीं-कहीं जड़ माहू का प्रकोप दिखाई दे रहा है।

भारत की जीत से वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में बड़ा बदलाव ऑस्ट्रेलिया से हारकर द. अफ्रीकी टीम तीसरे स्थान पर

एजेंसी ❑ दुबई

भारत ने बांग्लादेश को पहले टेस्ट में हरा दिया। वहीं, दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया ने भी घरेलू टेस्ट में दक्षिण अफ्रीका को दो दिनों में हरा दिया। इससे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के पॉइंट्स टेबल में बड़ा बदलाव हुआ है। ऑस्ट्रेलिया की जीत से टीम इंडिया को काफी फायदा पहुंचा है, जबकि खुद ऑस्ट्रेलियाई टीम का भी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचना लगभग तय हो चुका है। इस पूरे सीजन ऑस्ट्रेलियाई टीम शानदार फॉर्म में दिखी है। फाइनल मुकाबला अगले साल जून में ओवल में खेला जाएगा। भारत ने बांग्लादेश को चटगांव टेस्ट में 188 रन से हरा दिया। वहीं, ऑस्ट्रेलिया ने दक्षिण अफ्रीका को छह विकेट से हराया। इन दोनों मैच से पहले भारतीय टीम चौथे और दक्षिण अफ्रीका की टीम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के पॉइंट्स टेबल में दूसरे स्थान पर थी। वहीं, दोनों मैचों के नतीजे के बाद ऑस्ट्रेलियाई टीम 76.92 पॉइंट पर्सेंटेज के साथ शीर्ष पर काबिज है। वहीं, भारतीय टीम 55.77 पॉइंट पर्सेंटेज के साथ दूसरे स्थान पर पहुंच गई। दोनों मैचों के नतीजों के बाद दक्षिण अफ्रीका की टीम 54.55 पॉइंट पर्सेंट के साथ तीसरे स्थान पर लुढ़क गई है। श्रीलंका 53.33 पॉइंट पर्सेंटेज के साथ चौथे और इंग्लैंड 44.44 पॉइंट पर्सेंट के साथ पांचवें स्थान पर है। वहीं, पाकिस्तान की राह और मुश्किल हो गई है। टीम 42.42 पॉइंट पर्सेंट के साथ छठे स्थान पर है। बांग्लादेश से दोनों टेस्ट में हार से ही पाकिस्तान की टीम फाइनल में पहुंच पाती। हालांकि, ऐसा नहीं हुआ है। इंग्लैंड-पाकिस्तान सीरीज के बाद बांग्लादेश के खिलाफ टीम इंडिया की जीत और ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण अफ्रीका को हराने से अब भारतीय टीम डब्ल्यूटीसी के पॉइंट्स टेबल में अंतिम-दो में जगह बनाने की राह आसान हो गई है। भारत को अब कुल मिलाकर पांच टेस्ट खेलने हैं। बांग्लादेश के खिलाफ एक और टेस्ट के अलावा टीम इंडिया को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपने घर में चार टेस्ट मैचों की सीरीज खेलनी है। अगर टीम इंडिया सभी पांच मैच जीतने में कामयाब रहती है तो आसानी से फाइनल के लिए क्वालिफाई करेगी। वहीं, टीम इंडिया अगर इनमें एक भी टेस्ट गंवाती है तो उसे ऑस्ट्रेलिया बनाम दक्षिण अफ्रीका टेस्ट सीरीज पर निर्भर रहना होगा। दक्षिण अफ्रीका फिलहाल तीन मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलियाई दौरे पर है।

हालांकि, ऑस्ट्रेलियाई टीम जिस फॉर्म में है, दक्षिण अफ्रीका के लिए आगे की राह आसान नहीं रहने वाली है। अगर ऑस्ट्रेलिया दक्षिण अफ्रीका को क्लीन स्वीप करने में कामयाब रहता है और भारत सभी पांच टेस्ट जीतता है तो आसानी से फाइनल में पहुंच जाएगा। दक्षिण अफ्रीका के एक या दो टेस्ट जीतने पर टीम इंडिया की राह थोड़ी सी कठिन हो सकती है। दक्षिण अफ्रीका को ऑस्ट्रेलिया के बाद वेस्टइंडीज के खिलाफ अपने घरेलू मैदान पर टेस्ट सीरीज खेलनी है। ऑस्ट्रेलिया का फाइनल में पहुंचना लगभग तय माना जा रहा है। वहीं, दूसरे स्थान के लिए भारत, दक्षिण अफ्रीका और श्रीलंका के बीच टक्कर है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल जून 2023 में इंग्लैंड के ओवल स्टेडियम में खेला जाएगा। पिछला फाइनल 2021 में भारत और न्यूजीलैंड के बीच साउथैम्पटन में खेला गया था। न्यूजीलैंड ने टीम इंडिया को आठ विकेट से हराया था और टीम चैंपियन बनी थी।

'मार्टिनेज को 11 साल तक नहीं मिला मौका, 2021 में किया डेब्यू, दो साल में बदली मेसी की तकदीर

एजेंसी ❑ दोहा

अर्जेंटीना की टीम फीफा विश्व कप चैंपियन बन चुकी है। रविवार को हुए फाइनल मुकाबले में अर्जेंटीना ने गत विजेता फ्रांस को पेनल्टी शूटआउट में 4-2 से हरा दिया। इस विश्व कप में अर्जेंटीना की जीत में सबसे ज्यादा श्रेय 30 साल के गोलकीपर एमिलियानो मार्टिनेज को जाता है। न सिर्फ फीफा वर्ल्ड कप में बल्कि वह पिछले दो साल से मेसी और अर्जेंटीना की कामयाबी के पीछे अहम कारण रहे हैं। उन्होंने विपक्षी टीम के नाक में दम कर दिया। अर्जेंटीना की टीम को मेसी के रहते अलग-अलग टूर्नामेंट्स के चार फाइनल में जूझना पड़ा। इनमें 2007, 2015, 2016 में कोपा अमेरिका और 2014 में फीफा विश्व कप फाइनल में हार का सामना करना पड़ा। हालांकि, इन सालों में दो बातें समान रहीं। वह यह थी कि मेसी की अर्जेंटीना टीम किसी मेजर टूर्नामेंट के फाइनल तक तो पहुंची, लेकिन खिताब जीतने से चूक गई। वहीं, दूसरा यह कि इन सभी फाइनल्स में गोलकीपर एमिलियानो मार्टिनेज टीम में नहीं थे। 2021 में उन्हें अर्जेंटीना के लिए डेब्यू का मौका मिला और उन्होंने मेसी की तकदीर बदल दी। 2010 में मार्टिनेज ने प्रोफेशनल करियर की शुरुआत की थी। उन्होंने तब इंग्लिश फुटबॉल क्लब आर्सेनल जॉइन किया था। हालांकि, वह इस टीम में हमेशा रिजर्व गोलकीपर के तौर पर ही रहे। उन्हें 10 साल तक बेंच पर बैठाया गया। पहली बार उन्हें 2020 में आर्सेनल के लिए खेलने का मौका मिला। मैच था एफए कप फाइनल, जो कि आर्सेनल और चेल्सी के बीच खेला गया। नियमित गोलकीपर बर्न्ड लीनो के चोटिल होने पर मार्टिनेज को खेलने का मौका मिला और उन्होंने आर्सेनल को एफए कप चैंपियन बना दिया। यह मैच आर्सेनल ने 2-1 से अपने नाम किया था। इस प्रदर्शन के बाद भी उन्हें करीब एक साल तक अर्जेंटीना के लिए खेलने का मौका नहीं मिला। 2018 में रूस में हुए फीफा वर्ल्ड कप में एमिलियानो मार्टिनेज बतौर दर्शक अर्जेंटीना के मैच देखने के लिए पहुंचे थे। उनकी यह तस्वीर खूब वायरल हो रही है। तीन जून 2021 को चिली के खिलाफ फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशन मैच में मार्टिनेज पहली बार अर्जेंटीना के लिए खेलने के लिए मैदान में उतरे और कुछ ही दिनों में वह अर्जेंटीना के लिए हीरो बन गए। कोपा अमेरिका टूर्नामेंट में मार्टिनेज ने अपने दम पर टीम को जीत दिलाई। वह विपक्षी टीम के सामने मजबूत दीवार बनकर खड़े हो गए, जिसे ब्राजील के स्टार नेमार, कोलंबिया के जेम्स रॉड्रिगेज से लेकर विडाल तक नहीं भेद पाए। कोपा अमेरिका 2021 के सेमीफाइनल में अर्जेंटीना और मार्टिनेज के सामने कोलंबिया की चुनौती थी। यह मैच पेनल्टी शूटआउट तक पहुंचा था। अर्जेंटीना की टीम पूरी तरह से मार्टिनेज पर निर्भर थी और उन्होंने निराश नहीं किया। कोलंबिया के खिलाफ पेनल्टी शूटआउट में मार्टिनेज ने तीन सेव्स किए। पूरे टूर्नामेंट को मिलाकर मार्टिनेज ने चार पेनल्टी बचाए थे, साथ ही चार काउंटर अटैक पर भी सेव किए थे।

भारत-बांग्लादेश दूसरा टेस्ट : चाय तक बांग्लादेश की आधी टीम लौटी

12 साल बाद वापसी कर रहे उनादकट को 2 विकेट

मीरपुर। जयदेव उनादकट को डेब्यू के 12 साल बाद पहला टेस्ट विकेट मिला। वे 2 विकेट ले चुके हैं। जयदेव ने जाकिर हसन और मुश्फिकुर रहीम के विकेट लिए। भारत-बांग्लादेश टेस्ट सीरीज का दूसरा मुकाबला मीरपुर में खेला जा रहा है। बांग्लादेश ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला लिया है। पहले दिन दूसरे सेशन के बाद बांग्लादेश ने 5 विकेट पर 184 रन बना लिए हैं। मोमिनुल हक (65) और मेहदी हसन मिराज (4) नाबाद हैं। लिटन दास (25) को अश्विन ने राहुल के हाथों कैच कराया। उनसे पहले मुश्फिकुर रहीम (26 रन), कप्तान शाकिब अल हसन (16 रन), जाकिर हसन (15 रन) और नजमुल हसन शान्तो (24) पवेलियन लौट चुके हैं। 12 साल बाद टेस्ट टीम में वापसी कर रहे जयदेव उनादकट और आर. अश्विन ने दो-दो विकेट लिए हैं। उमेश यादव को एक विकेट मिला है। उनादकट ने 2010 में टीम इंडिया के साउथ अफ्रीका दौरे के पहले सेंचुरियन टेस्ट में डेब्यू किया था। डेब्यू मैच के 12 साल बाद उन्हें पहला टेस्ट विकेट मिला है।

मोमिनुल का 16वां अर्धशतक

मोमिनुल ने अपने टेस्ट करियर का 16वां अर्धशतक जमाया है। उन्होंने इस फॉर्मेट में 27वीं बार 50+ स्कोर बनाया है। सबसे ज्यादा 50+ स्कोर करने के मामले में वे 5वें नंबर के बांग्लादेशी बल्लेबाज हैं। उनसे ज्यादा तमीम इकबाल ने 41, शाकिल अल हसन ने 35, मुश्फिकुर रहीम ने 34 बार ऐसा किया है। जबकि हबीबुल बशर (27) बराबरी पर हैं।

पहला सेशन : मिला-जुला रहा

पहले दिन का पहला सेशन मिला-जुला रहा। इसमें जहां बांग्लादेशी टीम ने 82 रन जोड़े, वहीं भारतीय टीम के गेंदबाजों ने 2 विकेट चटकाए। एक समय बांग्लादेश के दोनों ओपनर 39 रन पर आउट हो गए थे।

ऐसे गिरे बांग्लादेश के विकेट...

पहला: जाकिर हसन कट करना चाहते थे। उन्हें केएल राहुल ने स्लिप पर कैच कराया।

दूसरा : शान्तो को अश्विन ने स्टम्प कराया।

तीसरा: कप्तान शाकिब अल हसन को उमेश यादव ने मिड ऑफ में पुजारा के हाथों कैच कराया।

चौथा : रहीम को उनादकट ने ऋषभ पंत के हाथों कैच कराया।

पांचवां: लिटन दास अश्विन की गेंद पर राहुल को कैच दे बैठे।

फ्रांस-अर्जेंटीना मैच को लेकर केरल में हिंसा, तीन लोगों पर चाकू से हमला, जश्न के दौरान लड़के की मौत

एजेंसी ❑ तिरुवनंतपुरम

फीफा विश्व कप के फाइनल में अर्जेंटीना ने गत विजेता फ्रांस को हराकर ट्रॉफी अपने नाम की। रोमांच से भरपूर इस मैच में कई टर्निंग पॉइंट्स आए। कभी ऐसा लगा कि अर्जेंटीना की टीम आसानी से जीत जाएगी, तो कभी फ्रांस ने वापसी कर पूरा पासा ही पलट दिया। ऐसे में मैच एक्स्ट्रा टाइम के बाद 3-3 की बराबरी पर खत्म हुआ और पेनल्टी शूटआउट तक पहुंचा। इसमें अर्जेंटीना ने 4-2 से जीत हासिल कर तीसरी बार विश्व कप खिताब भी जीत लिया।

दुनियाभर में इस जीत का जश्न मनाया गया। भारत में भी लोगों ने इस मैच का आनंद उठाया। मैच के बाद अर्जेंटीना और मेसी के फैन्स ने जीत का जश्न भी मनाया। खासतौर पर केरल में अर्जेंटीना की जीत का खूब जश्न मनाया गया। हालांकि, इस दौरान हिंसक घटनाएं भी सामने आई हैं। केरल के कन्नूर में फ्रांस और अर्जेंटीना के समर्थक आपस में भिड़ गए। इसमें तीन लोग घायल हो गए। पुलिस ने बताया कि उनमें से एक की हालत गंभीर है।

पुलिस के मुताबिक, यह घटना पल्लियामूला के पास की है। अर्जेंटीना के फैन्स ने फ्रांस के फैन्स पर तंज कसा, जिसके बाद हिंसा हुई। छह लोगों को हिरासत में लिया गया और जल्द ही उनकी गिरफ्तारी भी दर्ज की जाएगी। इसके अलावा कोच्चि और तिरुवनंतपुरम में भी हिंसा की कुछ घटनाएं सामने आईं। अर्जेंटीना की जीत के बाद जश्न मना रहे लोगों को संभालने के दौरान दो पुलिस अफसरों पर हमला हो गया। पुलिस ने बताया कि कोच्चि में एक सिविल पुलिस अधिकारी के साथ मारपीट की गई और उसे सड़क पर घसीटा गया। यह घटना तब घटी जब वह यातायात बाधित कर रही भीड़ को हटाने की कोशिश कर रहे थे। तिरुवनंतपुरम के पास पोझियूर में, एक सब-इंस्पेक्टर पर स्क्रीनिंग फाइनल के दौरान हमला किया गया।

कार्यक्रम स्थल पर हंगामा करने वाले दो युवकों को हटाने के दौरान दारोगा पर हमला किया गया। इसके अलावा पुलिस ने बताया कि कोल्लम में, एक स्थानीय स्टेडियम से अर्जेंटीना के प्रशंसकों के विक्ट्री मार्च के दौरान एक 17 वर्षीय किशोर अक्षय कुमार की मौत हो गई। अर्जेंटीना ने 1978 और 1986 के बाद 36 साल बाद फीफा विश्व कप जीता है। मेसी सात गोल के साथ टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा गोल करने में दूसरे नंबर पर रहे। फाइनल में फ्रांस के लिए हैट्रिक लगाने वाले किलियन एम्बाप्पे आठ गोल के साथ शीर्ष पर रहे।

पिछला एक साल डेट बाजार के लिए काफी अस्थिर रहा है, क्योंकि आरबीआई ने रेपो दर में पांच बार में 2.25 प्रतिशत बढ़त की

पिछले 10 साल में डेट फंड-सदाबहार निवेश का विकल्प, 9.3 फीसदी का सालाना रिटर्न मिला

एजेंसी ❑ नई दिल्ली

छोटी और लंबी अवधि की प्रतिभूतियों के बीच स्विच करने की सुविधा के कारण डायनॉमिक बॉन्ड फंड को अस्थिरता से निपटने का अच्छा तरीका माना जाता है। यह एक ओपन-एंडेड डेट स्कीम है। अपने पोर्टफोलियो में प्रतिभूतियों की परिपक्वता के लिहाज से प्रदर्शन करती है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि अधिकतम रिटर्न कहां अर्जित करने की उम्मीद है। फंड मैनेजर यह तय करता है कि कुछ महीनों में परिपक्व होने वाले बॉन्ड में निवेश करना है या कई वर्षों के बाद मैच्योर होने वाले बॉन्ड में। यही क्षमता उन्हें सबसे अनोखे प्रकार के डेट फंड उपलब्ध कराती है। इस फंड में सभी प्रकार के बाजार में उचित रिटर्न पैदा करने की क्षमता है। यह फंड ऐसे निवेशकों के लिए उपयुक्त है जिनको विभिन्न पोर्टफोलियो रणनीति के बीच स्विच करने की चिंता नहीं होती है। क्योंकि यह दूसरे पोर्टफोलियो में स्विच किए बिना निवेश में बने रहने में मदद करती है। साथ ही और कैसा भी बाजार हो यह एक तय आय देती है। अक्सर, निवेशक यह मान लेते हैं कि डेट निवेश का कोई मूल्य नहीं है, क्योंकि उनका रिटर्न इक्विटी के साथ कहीं भी मेल नहीं खाता है। हालांकि, मैक्रो-इकोनॉमिक कारकों के साथ-साथ ब्याज दर आपके डेट निवेश से मिलने वाले रिटर्न को तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस श्रेणी में कई स्कीम उपलब्ध हैं। उदाहरण के तौर पर आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ऑल सीजन्स बॉन्ड फंड इसमें शीर्ष पर है। इस श्रेणी में संपत्ति के मामले में सबसे बड़ी स्कीम भी है। इसका 10 वर्षों से अधिक का लगातार अच्छा ट्रैक-रिकॉर्ड रहा है। इसका कोई भी फैसला इन-हाउस मॉडल पर आधारित होता है जो कई छोटे बड़े कारकों को ध्यान में रखती है। दूसरा पहलू ब्याज दर पर आधारित है जो कॉर्पोरेट बॉन्ड और सरकारी प्रतिभूतियों के बीच निवेश करती है। जब ब्याज दरें अधिक होती हैं तो स्कीम लंबी अवधि की योजना बनाती है। तीन, पांच और दस वर्षों में फंड ने अपनी श्रेणी में क्रमशः 7.1त्न, 7.2त्न और 9.3त्न रिटर्न दिया है जो अन्य फंडों की तुलना में बेहतर है। इस फंड ने विभिन्न ब्याज दर के दौर में अवधि और कुछ विपरीत परिस्थितियों में भी नेट असेट वैल्यू (एनएवी) में वृद्धि प्रदान की है। एक सदाबहार डेट फंड लंबी अवधि में डेट साधन की क्षमता का दोहन करने के लिए उपयुक्त हो सकता है। डेट फंड की ऐसी श्रेणी को डायनॉमिक बॉन्ड फंड के रूप में जाना जाता है। यदि ब्याज दरें कम होने की उम्मीदें है, तो फंड मैनेजरों को अधिक लाभ पाने के लिए लंबी अवधि के बॉन्ड में निवेश करने की स्वतंत्रता है। एक निवेशक के रूप में, इस तरह के फंड में निवेश कॉल से लाभ उठाने के लिए कम से कम तीन साल या उससे अधिक समय तक निवेशित रहना आवश्यक है। यह मध्यम जोखिम क्षमता वाले निवेशकों के लिए उपयुक्त है। फंड को जो चीज सबसे अलग बनाती है वह यह है कि पोर्टफोलियो कॉल को इन-हाउस मॉडल के आधार पर लिया जाता है। इसमें एक से दस साल की अवधि का प्रबंधन करने की क्षमता है। ड्यूरेशन कॉल के लिए फंड इन-हाउस मॉडल पर निर्भर करता है। यह इन-हाउस मॉडल ब्याज दरों, चालू खाता घाटा, राजकोषीय घाटा, ऋण वृद्धि आदि जैसे मैक्रो कारकों को ध्यान में रखता है।

पांच वर्षों में 10 लाख करोड़ रुपये राइट ऑफ किए गए: वित्त मंत्री

एजेंसी ■ नई दिल्ली

अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों ने पिछले पांच वित्त वर्षों में 10,09,511 करोड़ रुपये राइट ऑफ कर दिए हैं और कर्जदारों से बकाया वसूली की प्रक्रिया जारी है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को लोकसभा को यह जानकारी दी। सीतारमण ने कहा कि राइट ऑफ किए गए कर्ज सहित एनपीए (नॉन परफॉर्मिंग एसेट) खातों में रिकवरी एक सतत प्रक्रिया है। उन्होंने कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के आंकड़ों के अनुसार, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने पिछले पांच वित्तीय वर्षों के दौरान 4,80,111 करोड़ रुपये की ऋण वसूली की है, जिसमें राइट ऑफ किए गए ऋणों के 1,03,045 करोड़ रुपये भी शामिल हैं। सीतारमण ने प्रश्नकाल के दौरान कहा, आरबीआई से प्राप्त जानकारी के अनुसार, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों ने पिछले पांच वित्तीय वर्षों के दौरान 10,09,511 करोड़ रुपये की राइट ऑफ कर दिया है। उन्होंने कहा कि बट्टे खाते में डाले गए ऋणों के कर्जदार पुनर्भुगतान के लिए उत्तरदायी बने रहेंगे और बट्टे खाते में डाले गए ऋण खातों में कर्जदारों से बकाये की वसूली की प्रक्रिया जारी है। सीतारमण ने कहा कि बैंकों ने उपलब्ध विभिन्न वसूली तंत्रों के माध्यम से बट्टे खाते में डाले गए खातों में शुरू की गई वसूली कार्रवाई को जारी रखा है। कार्रवाई में दीवानी अदालतों या ऋण वसूली न्यायाधिकरणों में मुकदमा दायर करना, वित्तीय संपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित अधिनियम, 2002 के तहत कार्रवाई, दिवाला और दिवालियापन संहिता के तहत राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण के तहत मामले दर्ज करना आदि शामिल है।

रिलायंस ने किया मेट्रो का अधिग्रहण: कंपनी को 31 लार्ज फॉर्मेट स्टोर का एक्सेस मिलेगा, 2,850 करोड़ रुपए में हुई डील

मुंबई। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की सहायक कंपनी रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड (RRVL) 2,850 करोड़ रुपए में फूड होलसेलर मेट्रो कैश एंड कैरी का अधिग्रहण करने जा रही है। इसके लिए एग्रीमेंट साइन किए गए हैं और रेगुलेटरी अप्रूवल के बाद मार्च 2023 तक इस डील के पूरी होने की संभावना है। जर्मनी की इस कंपनी ने 2003 में भारत में अपने ऑपरेशन शुरू किए थे और कैश-एंड-कैरी बिजनेस फॉर्मेट पेश किया था।

प्राइम लोकेशन स्टोर का मिलेगा एक्सेस: इस अधिग्रहण से रिलायंस रिटेल को दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद, कोलकाता, अमृतसर, अहमदाबाद, सूरत, इंदौर, मेरठ, लखनऊ, नासिक, विशाखापट्टनम, गुंटूर, विजयवाड़ा, तुमकुरु, गाजियाबाद और हुबली में मेट्रो के प्राइम लोकेशन पर मौजूद स्टोर का एक्सेस मिल जाएगा। डील के हिस्से के रूप में रिलायंस रिटेल को रजिस्टर्ड किराना स्टोर, संस्थागत ग्राहकों और एक मजबूत सप्लायर नेटवर्क का बड़ा बेस भी मिलेगा।

कंपनी के 31 लार्ज फॉर्मेट स्टोर: इस इंटरनेशनल फूड होलसेलर के देश के 21 शहरों में लगभग 3,500 एम्प्लॉइज के साथ 31 लार्ज फॉर्मेट स्टोर हैं। अभी तक स्न्ङ्क22 में मेट्रो इंडिया ने 29.8 मिलियन यूरो की बिक्री की है। इस अधिग्रहण से रिलायंस रिटेल के फिजिकल स्टोर फुटप्रिंट को और मजबूती मिलेगी। रिलायंस रिटेल वेंचर्स की डायरेक्टर ईशा अंबानी ने कहा, मेट्रो इंडिया भारतीय बी2बी बाजार में अग्रणी और प्रमुख खिलाड़ी है और इसने मजबूत ग्राहक अनुभव देने के लिए एक ठोस मल्टी-चैनल प्लेटफॉर्म बनाया है। हमारा मानना है कि भारतीय व्यापारी/किराना इको-सिस्टम की हमारी गहरी समझ और मेट्रो इंडिया के हेल्दी एसेट भारत में छोटे व्यवसायों की मदद करेगा। इसके पोर्टफोलियो में पहले से ही जियोमार्ट, आजियो, नेटमेड्स, और जिवामे जैसे अन्य ओमनीचैनल बिजनेस हैं। RRVL का 31 मार्च, 2022 को समाप्त वित्त वर्ष में लगभग 1,99,704 करोड़ रुपए का कंसॉलिडेटेड टर्नओवर और लगभग 7,055 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट था।

व्यापार सुगमता को बढ़ाने पर सरकार का जोर, दिवालिया कानून में संशोधन की तैयारी

एजेंसी ■ नई दिल्ली

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को कहा कि केंद्र सरकार सीमा शुल्क विभाग के अधिकारियों और व्यापार समुदायों समेत प्रत्येक हितधारक के लिए व्यापार सुगमता को बढ़ावा देने पर जोर दे रही है।वित्त मंत्री ने सीबीडीटी के नए कार्यालय की आधारशिला रखने के कार्यक्रम में कहा कि व्यापार गतिविधियों को सुविधाजनक बनाने पर सरकार ध्यान दे रही है। इस दिशा में प्रगति भी देखी गई है। नई इमारत बनाने के अलावा इस पर भी ध्यान दिया जा रहा है कि इमारतों को बिजली की कम खपत करने वाला कैसे बनाया जाए। उन्होंने कहा कि पहले कार्यालय बनाते समय अधिकारियों, कर्मचारियों और जरूरतों का ध्यान रखा जाता था। आज हम देखते हैं कि इमारतें कैसे हरित और ऊर्जा की कम खपत करने वाली बनेंगी। अब तो आयात-निर्यात एजेंट, महिला अधिकारियों व उनके बच्चों को भी ध्यान में रखते हैं। सरकार तनावग्रस्त संपत्तियों की समाधान प्रक्रिया में लगने वाले समय को घटाने के लिए दिवालिया एवं ऋणशोधन अक्षमता कानून (आईबीसी) में संशोधन की तैयारी कर रही है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, समाधान प्रक्रिया में देरी से इन संपत्तियों के मूल्य में गिरावट आ जाती है। इसे रोकने के लिए यह कदम उठाया जा रहा है।

भारत की वास्तविकता भ्रष्टाचार और गंदी सड़कें, युवा इसे बदलें: नारायणमूर्ति

एजेंसी ■ नई दिल्ली

दिग्गज आईटी कंपनी इंफोसिस के संस्थापक एनआर नारायणमूर्ति ने जीएमआर इंस्टीच्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के एक कार्यक्रम में छात्रों को संबोधित करते हुए कहा है कि भारत की वास्तविकता है भ्रष्टाचार, गंदी सड़कें, प्रदूषण और कई बार बिजली की अनुपस्थिति। वहीं, सिंगापुर की वास्तविकता है साफ सड़कें, प्रदूषण मुक्त वातावरण और बहुत सारी ऊर्जा। उन्होंने छात्रों से कहा, उस नई वास्तविकता को बनाने की जिम्मेदारी आपकी है। तस्र्क्की ओर से जारी एक विज्ञप्ति में यह बात कही गई है।

विजयनगरम जिले के राजम में जीएमआर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (जीएमआरआईटी) के रजत जयंती समारोह में छात्रों को संबोधित करते हुए नारायण मूर्ति ने कहा कि हर कमी कोबदलाव के अवसर के रूप में देखना चाहिए और %खुद को एक नेता के रूप में कल्पना करते हुए उस कमी को दूर करने की कोशिश करनी चाहिए, न कि किसी की प्रतीक्षा करनी चाहिए। नारायण मूर्ति ने आगे कहा कि युवाओं को समाज में बदलाव लाने की मानसिकता विकसित करनी चाहिए, जनता, समाज और राष्ट्र के हित को अपने व्यक्तिगत हित से ऊपर रखना सीखना चाहिए।

जीएमआर ग्रुप के अध्यक्ष जीएम राव का उदाहरण देते हुए उन्होंने छात्रों से उनसे प्रेरणा लेने और जब भी संभव हो एक उद्यमी बनने और अधिक रोजगार सृजित करने का आग्रह किया। उन्होने कहा, अधिक नौकरियों का सृजन गरीबी को दूर करने और कम विशेषाधिकार प्राप्त लोगों की मदद करने का एकमात्र समाधान है। इस दौरान जीएमआर समूह के अध्यक्ष जीएम राव ने कहा कि नारायण मूर्ति महत्वाकांक्षी युवाओं के लिए एक प्रेरणा हैं। उन्होने नारायण मूर्ति से कहा, आप मेरी टीम, सभी छात्रों और फैकल्टी के लिए एक प्रेरणा हैं। जीएमआर की स्थापना 1997 में हुई थी। तस्र्क्कग्रुप की कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आर्म - जीएमआर वरलक्ष्मी फाउंडेशन की ओर से संचालित संस्था अपनी स्थापना के 25 वें वर्ष का जश्न मना रही है।

भारत में रेपो रेट रिटेल महंगाई से 0.37% ज्यादा, नए साल में और महंगे नहीं लोन

नई दिल्ली। नए साल में लोन और महंगे नहीं होंगे। रेपो रेट में ज्यादा से ज्यादा 0.25त्न बढ़ोतरी हो सकती है। उसके बाद लंबे समय तक रिजर्व बैंक की नीतिगत दरें स्थिर रहेंगी। विश्लेषकों के मुताबिक, ये भी संभव है कि 2023 के आखिर तक ब्याज दरों में गिरावट शुरू हो जाए। इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि देश में रेपो रेट महंगाई दर से 0.37त्न ज्यादा हो गया है। इसे रियल सेंट्रल बैंक रेट कहा जाता है। इसके शून्य से ऊपर होने पर केंद्रीय बैंक अमूमन दरें बढ़ाना बंद कर देते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा की अर्थशास्त्री अदिति गुप्ता ने बताया कि अभी भारत समेत सिर्फ पांच बड़े देशों में रियल सेंट्रल बैंक रेट शून्य से ऊपर है। चीन, सऊदी अरब, ब्राजील और मेक्सिको इनमें शामिल हैं। रियल सेंट्रल बैंक रेट शून्य से नीचे आने पर करंसी की वास्तविक वैल्यू घटने लगती है। इसीलिए महंगाई बढ़ने पर रिजर्व बैंक रेपो रेट बढ़ाने लगता है, ताकि रियल सेंट्रल बैंक रेट शून्य से ऊपर रहे।

स्वत्वाधिकारी,मुद्रक,प्रकाशक एवं संपादक नागेश नरवरिया द्वारा जय माता प्रिंटर्स म.नं. 1 अमर दाल मिल के पास पेमदीपुरा चिकलोद रोड के पास बापू कालोनी जहांगीराबाद भोपाल मप्र से मुद्रित एवं म.नं. 51 एक्सटेंशन शिवलोक कॉलोनी फेस-3, खजूरी कलां रोड,तह. हुजूर जिला भोपाल से प्रकाशित। संपादक :- नागेश नरवरिया (समस्त विवादों का न्यायक्षेत्र भोपाल रहेगा।)